मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 34 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 20 – 26 अगस्त 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस भाषण: जमीनी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश.....3

बेन ब्रैडली: मेरठ षडयंत्र केस के अभियुक्त.....5

तोड़ी जा रही है स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली विरासत

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने 77वें स्वाधीनता दिवस पर केन्द्रीय पार्टी मुख्यालय अजय भवन पर झण्डारोहण किया। झण्डारोहण के दौरान भाकपा सचिवमंडल सदस्य नगेन्द्र ओझा, रामकृष्ण पांडा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, पार्टी कार्यकर्ता एवं इप्टा के साथी मौजूद थे।

डी राजा

15 अगस्त 1947 को हमें जो आजादी मिली, वह औपनिवेशिक जुए से मुक्ति के लिए लगभग एक सदी लंबे संघर्ष का परिणाम थी। हमारे देश को ब्रिटिश चंगुल से मुक्त कराने के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया और उनका बलिदान हमारी आजादी के रूप में फलीभूत हुआ। कम्युनिस्टों ने भारतीय स्वतंत्रता के अंतिम युद्ध, आरआईएन विद्रोह में अपनी ताकत दिखाकर अंग्रेजों को जाने को अपरिहार्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेताजी और आईएनए ने देश की आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन भारत एवं पाकिस्तान के रूप में हुआ। ब्रिटिश शासन की बुराइयों और विभाजन ने दो समुदायों के एक–दूसरे के प्रति रवैये को कठोर कर दिया और माहौल में हिंसा, आगजनी, हत्याओं और दुश्मनी की हवा भर गई।

उसी समय, जवाहरलाल नेहरू भारत को उसकी नियति की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और सरदार पटेल देश और उसकी सैकड़ों रियासतों को एकजुट करने के श्रमसाध्य प्रयासों में लगे हुए थे और कम्युनिस्ट जमीन पर रियासतों के खिलाफ लड़ रहे थे, यहां तेलंगाना में निजाम शासन के खिलाफ गौरवशाली संघर्ष का उल्लेख किया जा सकता है। कानून की किताबों से घिरे डॉ. अम्बेडकर संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे।

इस मुक्ति संघर्ष के हमारे अग्रणी नेता 15 अगस्त, 1947 के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन कलकत्ता में थे। देश के पूर्वी हिस्सों में हाल ही में रक्तपात देखा गया था, महात्मा गांधी हमारे नवजात राष्ट्र के सांप्रदायिक हिंसा के घावों पर मरहम लगाने के लिए उनके साथ थे। गांधी नोआखाली (अब बांग्लादेश में) गए जहां दंगे अपने चरम पर थे। पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण से क्रोधित भीड़ के गुस्से से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के संकल्प के साथ वह वहां शवों और बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के बीच थे। शांति के लिए उनकी अपील काम आई और अपने देश के लोगों के लिए उनकी चिंता सांप्रदायिक भीड़ पर भारी पड़ी। गांधी के उपवास का जनता पर असाधारण प्रभाव पड़ा और दोनों समुदायों के लोगों और नेताओं ने उनसे शांति बनाए रखने और दूसरे समुदाय के लोगों की रक्षा करने का वादा किया। हमारे लोगों की एकता में गांधी का साहस और दृढ़ विश्वास धर्मनिरपेक्षता और आपसी सम्मान का पुल बन गया, जिस पर हमारी अत्यधिक विविध आबादी ने स्वतंत्रता के लिए अपना पहला कदम उठाया।

इसके तुरंत बाद, गांधी एक और यात्रा पर निकल पड़े, इस बार उसी मिशन के साथ देश के उत्तर–पश्चिम में, सद्भाव स्थापित करना और लोगों को करीब लाना। मेवात क्षेत्र जो अब हरियाणा, यूपी और राजस्थान में है, वह आग की लपटों में घिरा था। सैकड़ों मुसलमान हिंसा के डर से पाकिस्तान भागने को तैयार थे। अलवर और भरतपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद उनकी चिंता बढ़ गई थी। गांधी ने मेव नेता चौधरी यासीन खान के आग्रह पर दंगाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया और 1947 में दिसंबर की कंपकंपाती ठंड में गुड़गांव के पास घासेरा गांव का दौरा किया।

धोती पहने गांधी ने जनता को संबोधित किया और अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की भारत की क्षमता के प्रति उनमें विश्वास जगाया। कमजोर गांधी ने कहा कि अगर मेरे पास कोई मौलिक शक्ति होती, तो एक भी मुसलमान को भारत से पाकिस्तान जाना या एक भी हिंदू या सिख को पाकिस्तान में अपना घर छोड़कर भारतीय संघ में शरण लेना जरूरी नहीं लगता। उन्होंने घोषणा की, 'भारत आपका है और आप भारत के हैं।' महान शांतिदूत ने लोगों को फिर से आश्वस्त किया। अल्पसंख्यक आबादी ने पाकिस्तान जाने के बजाय धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक भारत में रहने का फैसला किया। गांधीजी का वादा कायम रखा गया।

आज हम ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, जब देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' या साल भर चलने वाले इस उत्सव के समापन की ओर बढ़ रहा है।

भारत के पूर्वी भाग में स्थित मणिपुर जातीय संघर्ष का शिकार है। 3 मई को भड़की हिंसा ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए और पूरे राज्य को राहत शिविर बना दिया गया। सहानुभूति और करुणा राजनेता की कुशलता के लक्षण हैं, लेकिन आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों में इन गुणों की बेहद कमी है। गांधी जी द्वारा दिखाए गए एकता के साहस और चिंता का भाजपा के लिए कोई मतलब नहीं है जिनकी राजनीति झगड़े और विभाजन पर पलती है। प्रधानमंत्री का मणिपुर पर मुंह खोलना नग्न महिलाओं की परेड कराने के शर्मनाक वीडियो से कम शर्मनाक नहीं था। गृहमंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश ने आग में घी डालने का काम किया, यह स्वीकार करना था कि पहले से ही आग लगी थी। क्या सरकार आग लगने पर सोती हुई पकड़ी गई? नहीं, आरएसएस–बीजेपी के 'डबल इंजन' को चलाने के लिए नफरत के ईंधन की जरूरत है। वे चुनावी लाभ के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के लोगों को विभाजित कर रहे थे, जिसकी कीमत आज पूरा देश चुका रहा है। सहानुभूति का गांधीवादी स्पर्श अनुपस्थित है, डेमोगोगुरी और बयानबाजी घावों को ठीक नहीं कर सकती है। डबल इंजन ने मणिपुर को कलंकित कर दिया है।

हरियाणा की बात करें तो, जो कि आरएसएस की नीति के अनुसार हथियारयुक्त धर्म के इस्तेमाल का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है, वहां 31 जुलाई को 6 लोगों की मौत हो गई, जब एक कुख्यात, स्वघोषित गौरक्षक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें संघ परिवार के विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित धार्मिक जुलूस में लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया। बजरंग दल का यह विभाजनकारी नेता दो मुस्लिम व्यक्तियों के अपहरण और हत्या के मामले में वांछित है, जिनके शव एक कार में जले हुए पाए गए थे। तब से इस क्षेत्र में शांति नामुमकिन है और सामान्य स्थिति नदारद है।

दंगाई खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन हिंसा, आगजनी और पथराव के मामले सामने आ रहे हैं। समाज में बढ़ती इस खाई पर शासकों का जवाब संवाद और विश्वास बहाली नहीं है। यह बुलडोजर है। गांधी जी ने बहुत संवेदनशील समय में मेवात के लोगों के बीच पुल बनाए,

शेष पेज 15 पर...

संपादकीय

प्रधानमंत्री का सम्बोधनः जबर्दस्त नाकामियों को छुपाने की कोशिश

अगस्त का महीना हर भारतीय को स्वतंत्रता आंदोलन के महान संघर्षों और वीरतापूर्ण बलिदानों की अविस्मरणीय वीरगाथाओं की याद दिलाता है। इसी महीने भारत के लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारा स्वतंत्रता संग्राम एक अद्वितीय संघर्ष था जिसमें सत्याग्रह से लेकर सशस्त्र संघर्ष तक की विभिन्न धाराएं एक साथ बही, एक साथ मिली और देश को औपनिवेशिक जुए से आजाद कराया। यह संघर्ष उस ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ था जिसमें सूरज नहीं डूबता था। औपनिवेशिक उत्पीड़न के हिमायती समझते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का भारत के लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। परंतु औपनिवेशिक जुए से छुटकारा पाने की भारत के लोगों की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे एकताबद्ध हुए और वह प्राप्त किया जो असंभव नजर आता था। इस प्रकार 15 अगस्त भारत के इतिहास का एक सर्वाधिक प्रकाशमान दिवस बन गया।

15 अगस्त 1947 को अपने ऐतिहासिक भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को ''नियति के साथ मिलन'' का नाम दिया। अगले दिन, 16 अगस्त 1947 को लालकिले की प्राचीर से देश का संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि ''भारत का स्वतंत्र झंडा न केवल भारत के लिए बल्कि समूची दुनिया के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है''। हमारे इतिहास में इसके बाद सभी प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस पर सार्थक, प्रेरणात्मक और आत्मविश्लेषक भाषण की गौरवपूर्ण विरासत का अनुपालन करने की कोशिश की। नरेन्द्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर खोखले एवं कभी–कभी निरर्थक भाषण देना शुरू किया। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने यही किया। उसमें लफ्फाजी थी, हल्ला–गुल्ला था और कुछ भी सार्थक न था।

लालकिले से भाषण करते हुए नरेन्द्र मोदी भूल गए कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। वह शायद ही कभी इस तथ्य पर ध्यान देते हों कि उनके शब्दों को भारत के 140 करोड़ लोगों और एक शानदार भविष्य के लिए उनकी आशाओं–आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अपने उच्च पद को कलंकित करते हुए इस पवित्र अवसर पर उन्होंने अपना एक ठेठ राजनीतिक भाषण दिया जो शासक पार्टी का कोई भी प्रवक्ता दे सकता था। यह नाम बड़े और दर्शन छोटे होने का मामला था। उनके इस स्वतंत्रता दिवस भाषण में उनकी घबराहट और चिंता साफ दिखाई पड़ रही थी। जब उन्होंने दावा किया कि अगले साल भी वह स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करेंगे तो वह इस अवसर को राजनीतिक भविष्यवाणी के अवसर के तौर पर इस्तेमाल करते नजर आए। लोगों को दिखाई पड़ा कि 2024 के चुनाव के संबंध में वह कितने डरे हुए हैं। अपनी लफ्फाजी की महारत का इस्तेमाल कर वह अपनी चिंता और अनिश्चितता को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। यह कह कर कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वह जीवन के क्षेत्र में अपनी जबर्दस्त नाकामियों पर पर्दा डाल रहे थे। लोग उनके पहले किए गए वायदों और जमीनी हकीकत के बीच तुलना कर उनके निराधार दावों को समझ सकते हैं।

यह संयोगवश नहीं था कि जिस दिन हमने स्वतंत्रता हासिल की, उसी दिन प्रधानमंत्री ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत की चर्चा पर कोई अधिक बात नहीं की। अपने दिल में नरेन्द्र मोदी जानते हैं कि वह जिस राजनीतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी; जिस समय साम्राज्यवाद के खिलाफ घटनापूर्ण एवं विविधतापूर्ण संघर्ष चल रहा था, वह विचारधारा उसमें मूकदर्शक तक भी न थी। अतः उन्होंने लफ्फाजी का अपना आम रवैया अपनाया।

प्रधानमंत्री स्वयं को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके शासन के दौरान भारत में चमत्कार हो गया है। वह उतावले थे कि अन्य लोग भी यही समझें कि भारत में चमत्कार हो गया है। परंतु भारत की कठोर वास्तविकताएं लोगों को इस तरह के फर्जी प्रचार के खेल पर विश्वास करने की इजाजत नहीं देती। जिस समय प्रधानमंत्री ''विश्व मित्र'' और ''विश्व गुरु'' की शेखी बघार रहे थे, भारत के लोग अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। समूचा पूर्वोत्तर भारत अशांत है, मणिपुर राज्य जिसका उपरिकेंद्र है। जिस समय मणिपुर जल रहा था, उस समय महीनों तक अपनी खामोशी के संबंध में प्रधानमंत्री देश के लोगों के लिए जवाबदेह हैं। मणिपुर में जिन महिलाओं को निर्वस्त्र कर जबरन घुमाया गया, वह विकसित भारत के प्रधानमंत्री के तमाम दावों पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। मानव विकास सूचकांक में हमारा देश अत्यंत नीचे 132वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री संसद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की एक रिपोर्ट के बारे में शेखी बघार रहे थे। उसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार प्रति व्यक्ति नोमिनल जीडीपी में भारत 139वें स्थान पर है। शिशु मृत्यु दर के मामले में उप–सहारा क्षेत्र के देश भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं। दो करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का उनका वायदा झूठा साबित हो चुका है और हमारी युवा पीढ़ी एक अंधकारपूर्ण भविष्य का सामना कर रही है। महंगाई ने हर तबके के लोगों के रहन–सहन के हालात को डांवाडोल बना दिया है। तो भी हमारे देश के शासक दुनिया के सामने भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। ''सबका साथ और सबका विकास'' का प्रधानमंत्री का नारा उनके झूठे वायदों के कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने जो राजनीतिक भाषण दिया, वह एक नाकाम राजनेता द्वारा अपनी जबर्दस्त नाकामियों को छिपाने की एक दयनीय कोशिश था। इस बात ने लोगों को एकजुट होने और एक नए भारत के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता की एक बार फिर याद दिलाई।

आन्ध्र प्रदेश भाकपा ने जारी किया 'बस यात्रा' का पोस्टर

राम नरसिम्हा राव

विजयवाड़ाः वर्तमान लक्ष्य मोदी को सत्ता से हटाना है। मणिपुर पर मोदी की प्रतिक्रिया दुखद है। प्रवासियों को कोई सुरक्षा नहीं है। वायसीपी ने बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य की रक्षा करें और राष्ट्र को बचाएं, भाकपा राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने अपने भाषण में ये बातें कहीं। भाकपा राज्य सचिव रामकृष्ण और मुप्पल्ला नागेश्वर राव राज्य सहायक सचिव, भाकपा वहां उपस्थित थे। वे शनिवार को विजयवाड़ा के दसारी भवन में बस यात्रा के पोस्टर विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। बस यात्रा 17 अगस्त को शुरू होगी और 8 सितंबर को समाप्त होगी। यात्रा मोदी और जगनमोहन रेड्डी के कुशासन को उजागर करेगी। 12 अगस्त 2023 शनिवार को पोस्टर रिलीज हुआ। पोस्टर का विमोचन भाकपा के राष्ट्रीय सचिव बिनोय विश्वम ने किया।

भाकपा के राष्ट्रीय सचिव बिनोय विश्वम ने संबोधित करते हुए कहा है कि मणिपुर की घटना ने पूरे भारतीयों को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मसले पर बेहद व्यंग्यात्मक ढंग से सफाई दी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री दो घंटे से ज्यादा बोले, लेकिन मणिपुर के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर वह सिर्फ चार मिनट ही बोल सके। हालाँकि महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह और अधिकारी चुप थे। मोदी सरकार सात बहनें कहे जाने वाले उत्तर–पूर्वी राज्यों की खनिज और वन संपदा अपने कारपोरेट यारों को सौंप रही है। रोजगार की संभावनाएं धीरे–धीरे कम होती जा रही हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कानूनों को बदलकर उन्हें नए नाम दिए जाएं बल्कि युवाओं, गरीबों और प्रवासी लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि संसद में कई विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किये गये। बस यात्रा 17 अगस्त से 8 सितंबर तक आंध्र प्रदेश के सभी जिलों को कवर करते हुए निकलेगी। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए भारतीय विपक्ष उचित तरीके से काम कर रहा है। संसद में वाईएसआरसीपी का पूरा शरीर जगन के साथ है लेकिन मन मोदी के साथ है।

भाकपा राज्य सचिव के रामकृष्णा ने अपने संबोधन में कहा कि जगनमोहन रेड्डी सरकार उल्टे गेयर में चल रही है। महज चार महीने की अवधि में उन पर 33,500 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। चार साल की अवधि में उन्होंने एक भी सिंचाई परियोजना पूरी नहीं की है। पोलावरम परियोजना हवा में छोड़ दी गई है। रामकृष्णा ने पूछा कि यह परियोजना केंद्र सरकार को क्यों नहीं सौंपी जाती। जगन ने वादा किया है कि पोलावरम को 2020, 2021, 2022 के खरीफ सीजन तक पूरा किया जाएगा। लेकिन अब जगन ने कहना शुरू कर दिया कि पोलावरम को 2025 तक पूरा किया जाएगा। हालांकि 2024 तक जगन को अपने पैतृक घर जाना होगा। वाईएसआरसीपी की नीतियों के कारण ताइवान की कंपनी तमिलनाडु चली गई है, अमरराजा बैटरी प्लांट तेलंगाना चला गया है। अनंतपुर में जैकी और केआईए कंपनियां बिल्कुल भी निवेश नहीं कर रही हैं। तेलंगाना में 2.2 लाख करोड़ का आईटी निर्यात है जबकि आंध्रप्रदेश में 2000 करोड़ का भी आईटी निर्यात नहीं है। राज्य में 35 फीसदी बेरोजगार हैं। उन्हें नौकरी मुहैया करायी जानी चाहिए।

प्रदेश में टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। वाईएसआरसीपी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पर हमला किया लेकिन उल्टे चंद्रबाबू पर हत्या के प्रयास का आपराधिक मामला कायम कर दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करने वाली बस यात्रा 17 अगस्त को विजाग स्टील प्लांट के गेट से शुरू होगी और 8 सितंबर को विशाल सार्वजनिक बैठक के साथ तिरुपति में समाप्त होगी। चूंकि जगन को केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उन पर कई करोड़ रुपये का कर्ज हो सकता है। एनडीए के बाहर किसी भी पार्टी ने भाजपा का ऐसा समर्थन नहीं किया है जैसा कि वाईएसआरसीपी समर्थन कर रही है। रामकृष्णा ने कहा कि यही कारण है कि जगन के खिलाफ मामले आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस भाषण : जमीनी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश

डॉ. संतोषकुमार महापात्रा

15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से 10वीं बार स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले यह उनका अंतिम स्वतंत्रता दिवस भाषण था। उनका भाषण लगभग 90 मिनट चला।

भाष्ण में उन्होंने जो बातें कही, न तो वह साक्ष्य–आधारित थी और न तथ्य–आधारित। उनमें उनकी लफ्फाजी में महारत के अलावा कुछ न था। उन्होंने अपने कार्यनिष्पादन के संबंध में लंबे–चौड़े वादे किए जो तथ्य और आंकड़ों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। यह जमीनी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश के अलावा कुछ न था।

उन्होंने भ्रष्टाचार/भाई–भतीजावाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण को तीन पापों की संज्ञा दी और उनसे छुटकारा पाने का आह्वान किया। पर प्रश्न यह है कि यदि वह परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं तो इसे अपनी स्वयं की पार्टी में क्यों नहीं रोकते। प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी का परिवारवाद और भाई–भतीजावाद क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्या उन्हें नहीं मालूम कि भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का एक बेटा संसद सदस्य है। दूसरा बेटा विधायक है।

मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश गोयल के पुत्र हैं। मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री धर्मेन्द प्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे देवेन्द्र प्रधान के पुत्र हैं।

मोदी सरकार में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल के पुत्र हैं। मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू के पिता अरूणाचल विधान सभा के प्रो टैम स्पीकर रहे हैं।

मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे अैर भाजपा की बड़ी नेता विजयराजे सिंधिया के पौत्र हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद पूर्व केंदीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितेन्द्र प्रसाद के पुत्र हैं।

हजारीबाग से भाजपा के सांसद और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे जयंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिंह के पुत्र हैं। भाजपा संसद सदस्य प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता साहिब सिंह के पुत्र हैं।

महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं) विधान परिषद सदस्य रहे गंगाधरपंत फडणवीस के पुत्र और राज्य मंत्री शोभा फडणवीस के भतीजे हैं। भाजपा संसद सदस्य विवेक ठाकुर अटलबिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता सी.पी. ठाकुर के पुत्र हैं।

भाजपा सांसद नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र हैं। भाजपा संसद सदस्य दुष्यंत सिंह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसंधुरा राजे सिंधिया के पुत्र हैं।

उत्तर प्रदेश में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हैं। भाजपा संसद सदस्य सनी देओल भाजपा के पूर्व संसद सदस्य धर्मेन्द्र कुमार के पुत्र हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह के पुत्र राजबीर सिंह और पौत्र संदीप सिंह भी भाजपा राजनीति के कारोबार में है।

भाजपा के संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों में ऐसे लोगों की फहरिस्त काफी लंबी हैं जो केवल परिवारवाद के ही कारण राजनीतिज का कारोबार कर रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री समेत भजपा के किसी भी नेता को यह झूठा दावा करने में कोई झिझक नहीं होती कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है।

परिवारवाद की राजनीति गांधी परिवार तक सीमित नहीं है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अनेक राजनीतिक नेता परिवारवाद की राजनीति को पालते–पोसते हैं।

आज प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कहते हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने का वायदा किया था पर ऐसा करने में नाकाम रहे। कोई भ्रष्ट नेता उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वह तुरंत दूध का धुला हो जाता है और उसे हर सजा से छूट मिल जाती है। उनके समय में भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद पहले से कहीं अधिक बढ़ा है परंतु जैसा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से पता चलता है वह अलग–अलग रूपों में है। पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (2021 में भारत का स्थान 180 देशों में 85वां है। 2014 में भी इसी स्थान पर था। पिछले साल 86वें स्थान पर था।)।

ट्रांसपैरेंसी इन्टरनेशनल के अनुसार, भारत के लोकतांत्रिक स्टेट्स के संबंध में चिंताजनक स्थिति है क्योंकि मूलभूत स्वतंत्रताओं और संस्थागत नियंत्रण और संतुलन का क्षरण हो रहा है। चुनावी बॉडों के तरीके से शासक पार्टी को अपारदर्शी तरीके से पैसा पहुंच रहा है। राजनीतिक चंदों का बड़ा हिस्सा शासक पार्टी के पास पहुंचता है।

2014 के बाद के पिछले 9 वित्त वर्षो में 14.56 लाख करोड़ रुपए का एनपीए बट्टेखाते में डाल दिया गया है। 7 अगस्त 2023 को संसद में बताया गया कि इस 14.56 लाख करोड़ रुपए में बड़े उद्योगों एवं सेवाओं के बट्टेखाते में डाले गए एनपीए की मात्रा 7.41 लाख करोड़ रुपए है। बट्टेखाते में डाली गई कुल रकम का मात्र 13 से 15 प्रतिशत बाद में वसूल किया जा सका। क्या यह एक बड़ा घोटाला नहीं? क्या शासक पार्टी की मदद के बगैर किसी का बैंक से लिया कर्ज इस तरह बट्टेखाते में डाला जा सकता है?

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हमारे बजट का आकार कम हो रहा है। कर्ज बढ़ रहा है। उसका ब्याज तक चुकाना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि पिछले 9 साल में कर्ज में 174 प्रतिशत की वृद्धि क्यों हुई?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च 2014 को केंद्र सरकार के ऊपर 58.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था जो सकल घरेलू उत्पाद का 52 प्रतिशत था; 31 मार्च 2023 को वह बढ़कर 155.6 लाख करोड़ रुपए हो गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 57.1 प्रतिशत है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार पर बाहरी कर्ज 2013–14 में 374,448 करोड़ रुपए था जो 2022–23 में 100 प्रतिशत बढ़कर 7,48,895 करोड़ रुपए हो गया।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर भारत का सरकारी स्वास्थ्य खर्च दुनिया में सबसे कम है। निजीकरण के कारण शिक्षा समाज के काफी बड़े तबके के लिए पहुंच से बाहर हो गई है। अमीर आदमी से टैक्स कम और गरीब से अधिक लिया जा रहा है। 2021–22 में जीएसटी से मिलने वाले कुल टैक्स 14.83 लाख करोड़ रुपए का 64 प्रतिशत हिस्सा आबादी के सबसे नीचे के 50 प्रतिशत हिस्से से आया। अनुमानों के अनुसार, जीएसटी का 33 प्रतिशत हिस्सा 40 प्रतिशत मध्यम वर्ग से आता है और शीर्ष के 10 प्रतिशत से उसका केवल 3 प्रतिशत हिस्सा आता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहां महंगाई कम है। परंतु 15 अगस्त को ही समाचार पत्रों ने बताया कि जुलाई में महंगाई 15 महीने के सबसे उच्च स्तर 7.44 प्रतिशत पर थी। खाद्य पदार्थो की महंगाई, जो गरीब लोगों पर सबसे ज्यादा चोट करती है, दो अंकों में है। पिछले कुछ सालों में सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं के दाम दो से तीन गुना बढ़ चुके है।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी गारंटी है कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने 2019 में दावा किया था कि 2024 में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा परंतु 2023 में नोमिनल जीडीपी केवल 3.75 ट्रिलियन डॉलर ही रही।

नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार के 9 वर्षो में जीडीपी वृद्धिदर औसतन 5.7 प्रतिशत के लगभग रही जबकि यूपीए की सरकार के कार्यकाल में यह वृद्धि दर औसतन 6.7 प्रतिशत थी। ऐसे में सरकार कैसे दावा कर सकती है कि अर्थव्यवस्था को पहले की सरकार से बेहतर तरीके से संभाल रही है?

विकास के संबंध में लंबे–चौड़े दावे करते समय प्रधानमंत्री को नहीं भूलना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आमदनी में भारत का स्थान दुनिया में 139वां है यानी बंगलादेश से भी नीचे जो 138वें स्थान पर है। क्रयशक्ति समानता के लिहाज से प्रतिव्यक्ति आमदनी के मामले में भारत में दुनिया में 127वें स्थान पर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया हमारी तरफ हमारी प्रतिबद्धता के कारण देख रही है। परंतु वास्तविकता इससे अलग है। भारत में भूखे, गरीब और आवासविहीन लोगों की सबसे बड़ी तादाद है। भारत के 97 करोड़ लोग स्वस्थ भोजन से वंचित है। करोड़ों लोग नहीं जानते कि उन्हें अगली बार भोजन कब और कैसे मिलेगा?

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत का स्थान अत्यंत नीचा है। विश्व भूख सूचकांक (2022) में भारत 116 देशों में 107वें स्थान पर, मानव विकास सूचकांक (2021–22) में 191 देशों में 132वें स्थान पर, टिकाऊ विकास सूचकांक (2022) में 163 देशों में 120वें स्थान पर, विश्व प्रसन्नता सूचकांक (2023) में 149 देशों में 126 वें स्थान पर और विश्व शांति सूचकांक (2022) में 163 देशों में 136वें स्थान पर है। इन सूचकांकों से पता चलता है कि वृद्धि लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी को नहीं झलकाती। इसी प्रकार, भूमंडलीय लिंग अंतर सूचकांक (2022) में भारत146 देशों में 135वें स्थान पर और लिंग समानता सूचकांक में 129 देशों में भारत 95वें स्थान पर है।

भूल जाएं कि भारत एक विकसित देश बन रहा है। आमदनी स्तर द्वारा देशों के विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार, अन्य 46 देशों के साथ भारत आज भी एक निम्न–मध्य–आय देश है, जबकि 2020 के वित्त वर्ष में श्रीलंका उच्च–मध्य–आय वर्ग में पहुंच चुका है।

प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व में विकास की चर्चा भी की। पिछले साल उन्होंने कहा था ''नारी तू नारायणी''। पर उनके कार्य काल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इसे मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार एवं अत्याचार से समझा जा सकता है। 2021 में महिलाओं के विरूद्ध अपराध में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, महिलाओं के विरूद्ध 2020 में अपराध के 3,71,503 मामले हुए थे,2021 में बढ़कर 4,28,278 हो गए। 2020 के मुकाबले 2021में बलात्कार के मामलों की संख्या 19.34 प्रतिशत बढ़कर 31,677 पर पहुंच गई यानी प्रतिदिन बलात्कार के लगभग 87 मामले सामने आ रहे हैं। समाज में अपराध बढ़ रहा है, आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये ''अमृतकाल'' है।

मणिपुर के संबंध में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां स्थिति सुधर रही है और शीघ्र ही शांति बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के लोग मणिपुर के साथ खड़े हैं। परंतु मणिपुर 3 मई से जल रहा है, वहां डबल इंजन की सरकार है और ऐसा नजर नहीं आता कि केंद्र सरकार ने वहां के हालात सुधारने के लिए कोई सार्थक कदम उठाए हों। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री की पार्टी की फूटपरस्त नीतियों के कारण ही मणिपुर इस हाल पर पहुंचा।

प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर भारत की अनूठी पहचान को रेखांकित किया और कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता है। कुछ समय पहले उन्होंने भारत के लोकतंत्र की जननी कहा था। परंतु उनके कार्यकाल में लोकतंत्र के सभी स्तंभ क्षरण का शिकार हुए हैं। शासक पार्टी परस्त लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

उनके कार्यकाल में विभिन्न संस्थाओं की स्वायत्ता एवं निष्पक्षता का क्षरण हुआ है। ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का दुरूपयोग किया जा रहा है। विरोध और विपक्ष को कुचलने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों का दुरूपयोग किया जा रहा है। समाज में फूटपरस्ती फैलाई जा रही है। चुनावी फायदे के लिए मतदाताओं का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ाया जा रहा है। सांप्रदायिक झगड़े पैदा किए जा रहे हैं जिससे देश की एकता एवं अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा

शेष पेज 14 पर...

म.प्र. महिला कैडर्स के प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन

उमरिया: मध्य प्रदेश की महिला कैडर के लिए तीन दिवसीय पार्टी क्लास का आयोजन राज्य के उमरिया जिले के घुन घुटी के जंगल रिसॉर्ट में सफलतापूर्वक किया गया।

तीन दिवसीय कक्षा का उद्घाटन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मप्र राज्य परिषद के सहायक सचिव हरिद्वार सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भाकपा के केंद्रीय शिक्षा विभाग के सदस्य डॉ. युगल रायलू ने की।

अपने उद्घाटन भाषण में हरिद्वार सिंह ने कक्षा को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से आने वाले समय की अच्छी नेता बनने के लिए मार्क्सवादी दर्शन से परिचित होने का आह्वान किया। उन्होंने भाकपा के महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने हर मुश्किल समय में पार्टी का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि महिला कैडर की क्लास होने के नाते, महिलाओं के मुद्दे इस क्लास में महत्वपूर्ण होंगे। मार्क्सवादी दर्शन के अलावा प्रतिभागियों को उन चुनौतियों को समझने का प्रयास करना चाहिए जिनका आज भारत की महिलाएं सामना कर रही हैं। हरिद्वार सिंह ने पार्टी की राज्य परिषद सदस्य एवं राज्य आंगनबाडी संघ की महासचिव विभा पांडे के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने अधिकतम महिला कैडर तक पहुंचने की कोशिश की।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. युगल रायलु ने राज्य परिषद के सचिव अरविन्द श्रीवास्तव एवं सहायक सचिव हरिद्वार सिंह, को क्लास के सफल

हरिद्वार सिंह

आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे उपलब्ध पुस्तको को पढ़ें। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद को समझना और उस पर अमल करना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए हमें बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों को तीन दिनों की छोटी अवधि में प्रभावी अध्ययन के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन किया।

विभा पांडेय को कक्षा का मॉनिटर चुना गया। अरुणा पटेल को वर्ग का सहायक मॉनिटर चुना गया। इन दोनों ने कक्षा की कार्यवाही का संचालन किया।

पहला सत्र डॉ. रायलु द्वारा 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' विषय पर था। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा को समझने के लिए, तर्क के बुनियादी सिद्धांतों को समझाया। जब उन्होंने प्रतिभागियों से प्रत्येक से तार्किक और अतार्किक घटनाओं का एक उदाहरण देने को कहा, तो सहजता से प्रत्येक प्रतिभागी ने कई घटनाओं के बारे में बताया और चर्चा की।

एडवोकेट अरुणा पटेल ने दूसरे सत्र में 'महिलाओं के संवैधानिक अधिकार' विषय पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने भारतीय संविधान में निहित महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाया।

विभा पांडे ने दिन का समापन 'दैनिक जीवन में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना' विषय पर अपने सत्र के साथ किया। यह एक इंटरैक्टिव सत्र था जिसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिय।

दूसरे दिन सारिका श्रीवास्तव ने अपने सत्र में 'महिलाओं के संघर्ष के इतिहास' पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से शुरू करते हुए विषय पर विस्तार से जानकारी दी। हरिद्वार सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास और श्रमिक आंदोलन पर एक सत्र आयोजित किया। अपने अत्यंत ज्ञानवर्धक व्याख्यान में हरिद्वार सिंह ने छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम और ट्रेड यूनियन आंदोलन में कम्युनिस्टों द्वारा निभाई गई वीरतापूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कक्षा को गर्व से बताया कि आज भारत की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन एटक की संतान हैं। उन्होंने बताया कि आठ घंटे कार्य दिवस शुरू करने का श्रेय एटक को जाता है। डॉ.रायलु ने अंतिम सत्र में मार्क्सवाद की मूल बातें बताईं। उन्होंने प्रतिभागियों को बुर्जुआ पार्टियों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के फर्क को समझाया। किरण प्रकाश ने फीडबैक सत्र का संचालन किया जिसमें सभी प्रतिभागियों ने कक्षा में अपने अनुभव के बारे में बात की। अधिकांश प्रतिभागियों ने वादा किया कि वे राज्य में पार्टी को खड़ा करने के लिए गंभीरता से काम करेंगे। तीन दिवसीय कक्षा में मध्य प्रदेश के दस जिलों से 40 महिलाओं ने भाग लिया।

दो युवा वकील अनामिका तिवारी और कोमल यादव सबसे कम उम्र की प्रतिभागी थीं। शहडोल के अमजोर से अपनी स्कूटी पर 100 किमी की दूरी तय कर आई पुष्पा के उत्साह की सभी ने सराहना की।

रानी द्विवेदी, अर्चना चौधरी, कौशल यादव, अंजलि श्रीवास्तव, अनिता सिंह, शिवकली साकेत, अंजना द्विवेदी और संजय नामदेव ने कक्षा की सफलता के लिए कड़ी मेहनत की।

भाकपा, माकपा एवं किसान मोर्चा का हाथरस कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

हाथरस, 9 अगस्त 2023: भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आज–विदेशी कंपनियां भारत छोड़ें, भाजपा सरकार गद्दी छोड़ो, मणिपुर की जनता को न्याय दो, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बन्द करो, महंगाई पर रोक लगाओ, बेरोजगारों को काम दो, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करो, गरीबों को राशन की दुकान पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराओ, बुलडोजर से गरीबों के आशियाने ढहाने की कार्यवाही रोको, नूंह दंगे के मास्टरमाइंड बजरंग दलियों को भी गिरफ्तार करो, सांप्रदायिक सौहार्द से खिलवाड़ बन्द करो आदि नारों के साथ भाकपा, माकपा और संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज हाथरस कलेक्ट्रेट पर जंगजू प्रदर्शन किया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त स्थानीय मांगों को सम्मिलित कर एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट के अधिशासी अधिकारी को सौंपा।

जिसमें जिले की जीर्ण शीर्ण सड़कों, सासनी नानऊ मार्ग के पुनर्निर्माण और विकास, मुफ्त बिजली की सरकारी घोषणा के बावजूद किसानों पर आ रहे बिजली के बिल, ईंधन के नाम पर बिजली के रेट बढ़ाने की कोशिश शामिल है।

स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ जम्मू भाकपा का प्रदर्शन

जम्मू: भाकपा की जम्मू इकाई ने गांव मरालिया में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा रीजनल सचिव राकेश शर्मा (सदस्य राष्ट्रीय परिषद, सीपीआई)। प्रदर्शन के समय राकेश ने निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की।

कई वर्षों से बिजली, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे, बिजली के तारों के लिए कोई उचित बुनियादी ढांचा नहीं है लेकिन सरकार जबरन स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों ने संकल्प लिया कि जब तक लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता या उचित बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो जाता, तब तक लोग अधिकारियों को स्मार्ट मीटर लगाने का काम आगे नहीं बढ़ने देंगे।

कम्युनिस्ट नेताओं की जीवनी–84

बेन ब्रैडली : मेरठ षडयंत्र केस के अभियुक्त

अनिल राजिमवाले

बेन ब्रैडली प्रसिद्ध ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्होंने भारत के मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलन में लंबे समय तक काम किया और प्रसिद्ध मेरठ षडयंत्र केस (1929–33) में अभियुक्त कैदी बने। रजनी पाम दत्त के साथ दत्त–ब्रैडली थीसिस के वे सह–लेखक भी थे। उनका जीवन सीपीआई के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ था।

प्रारंभिक जीवन

बेंजामिन फ्रांसिस ब्रैडली का जन्म 1 जनवरी 1898 को वाल्थमस्टो, लंदन में हुआ था। उनका परिवार एक श्रमिक परिवार था। उनके पिता टाइम–कीपर और रात्रि प्रहरी थे। वे आठ भाई–बहन थे, उनमें से दो की बचपन में ही मृत्यु होगई। इंजीनियर के प्रशिक्षु के रूप में काम करने के लिए बेन ने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रिटिश नौसेना में सेवा की। इसके बाद वह खुद एक इंजीनियर बन गए, और 1920 में इसकी स्थापना के बाद से अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (एईयू) के सदस्य भी बन गए। वह धातु श्रमिकों के आंदोलन में भी सक्रिय थे।

राजनीति में प्रवेश : भारत–यात्रा

बेन पहली बार 1921 में दो साल के अनुबंध के तहत एक इंजीनियर के रूप में भारत आए, और रावलपिंडी में एक बड़ी कार्यशाला की देखरेख करते हुए काम किया। उन्होंने स्वयं भारतीय श्रमिकों की भयानक स्थितियों को देखा। 1923 में ब्रिटेन लौटने पर वह ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीजीबी) में शामिल हो गए। उनकी गतिविधि का मुख्य क्षेत्र ट्रेड यूनियन आंदोलन था वह एक इंजीनियरिंग वर्क्स में एक दुकान के प्रबंधक थे।

भारत वापस

उस समय सीपीजीबी और सीपीआई के बीच बहुत करीबी और सक्रिय सहयोग था। सीपीजीबी ने इसके निर्माण में भारतीय ट्रेड यूनियनवादियों और कम्युनिस्टों की मदद की। आंदोलन और संगठन में सहायता के लिए कम्युनिस्टों सहित कई ब्रिटिश ट्रेड यूनियनवादी भारत आए और जमीनी स्तर पर काम किया। बेन ब्रैडली, फिलिप स्प्रैट के साथ, 1927 में औद्योगिक श्रमिक वर्ग के बीच काम करने के लिए भारत आए। एक अन्य ब्रिटिश ट्रेड यूनियनिस्ट लेस्टर हचिंसन भी थे। ब्रैडली एआईटीयूसी से संबंधित बंबई ट्रेड यूनियनों से जुड़ गए, और जल्द ही 1927 में उन्हें एआईटीयूसी की कार्यकारिणी समिति में शामिल कर लिया गया। वे बंबई में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी (डब्लूपीपी) अर्थात मजदूर किसान पार्टी के उभरते समूह से भी जुड़ गए।

उस समय बंबई प्रांतीय कांग्रेस में वामपंथी तत्वों के एक बड़े हिस्से ने समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया था। जल्द ही उन्होंने डब्ल्यूपीपी की स्थापना की। जिसके बेन एक सक्रिय नेता गए। शीघ्र ही उन्हें इसकी कार्यकारिणी में सम्मिलित कर लिया गया।

बेन 1928 में स्थापित नवगठित गिरणी कामगार यूनियन (जीकेयू) में बहुत सक्रिय थे। एस ए डांगे, एसवी घाटे, मिरजकर और अन्य नेताओं के नेतृत्व में लाखों मिल मजदूर सड़कों पर थे। ब्रैडली अग्रणी शख्सियतों में से थे। उन्होंने मजदूरों की चलों और फैक्ट्री के गेट पर कई भाषण दिये। वह चॉलों में उनके बीच में भी रहे और उन्हें जीकेयू में संगठित किया। वे इसके उपाध्यक्ष भी बने।

हैंडबिल और पैम्फलेट बड़ी संख्या में उनके और अन्य नेताओं के नाम से संयुक्त रूप से जारी किए गए थे। जैसा कि हम देखेंगे, मेरठ षडयंत्र केस में उनका बयान बहुत ही ज्ञानवर्धक है।

मेरठ षडयंत्र केस में (1929–33)

मार्च 1929 में बेन ब्रैडली को देश भर से 30 अन्य कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ पुलिस ने पकड़ लिया। उनमें दो अन्य ब्रिटिश कम्युनिस्ट शामिल थे फिलिप स्प्रैट और लेस्टर हचिंसन। ब्रैडली को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई।

गिरफ्तार किए गए लोगों में कम्युनिस्ट, एआईसीसी के सदस्य, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी (डब्ल्यूपीपी) के नेता और कपड़ा, लौह कारखाने, रेलवे और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के शीर्ष ट्रेड यूनियन नेता और एआईटीयूसी के पदाधिकारी शामिल थे।

ब्रैडली और अन्य की गिरफ्तारी पर भारत और इंगलैंड दोनों जगह विरोध प्रदर्शन हुए। अप्रैल 1929 में एक जुलूस निकला, लंदन में विक्टोरिया स्टेशन से मार्बल आर्क तक। ब्रिटिश पुलिस ने बलपूर्वक सभी जातीय भारतीयों को क्षेत्र से हटा दिया। पूरे ब्रिटेन में भारतीयों और अंग्रेजों ने मेरठ षडयंत्र केस के कैदियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया।

केएफ नरीमन की अध्यक्षता में एक मेरठ रक्षा एवं राहत समिति का गठन किया गया।

धन भी एकत्र किया गया। हचिंसन की माँ श्रीमती नाइट ने मेरठ के कैदियों की रिहाई के लिए इंग्लैंड में बहुत काम किया। उन्होंने सांसदों को प्रश्न पूछने के लिए सामग्री उपलब्ध करायी।

मामले की कार्यवाही में अपने भाषण (बयान) में ब्रैडली ने ब्रिटेन और भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन और अनपढ़ भारतीय श्रमिकों की आशाओं के साथ विश्वासघात का वर्णन किया। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन, जो हाल तक प्रतिबंधित था, इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गया कि ब्रिटिश शासक चिंतित हो गए और मेरठ षडयंत्र मामलों के जरिए उन पर हमला किया।

ब्रैडली भारत में टीयू आंदोलन के इतिहास पर कई अज्ञात या कम ज्ञात तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा: 'अखिल भारतीय

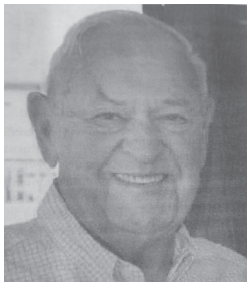

टीयूसी का पहला सत्र जिसमें मैंने भाग लिया था वह 1927 में कानपुर सत्र था।' वह भारतीय टीयू आंदोलन से संपर्क करने और यह देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि यह कैसे काम करता है।

इसलिए, मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी, जो टीयूसी के कानपुर सत्र की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, से भाग लेने की अनुमति मांगी.....' उन्हें अनुमति मिल गई।

ब्रैडली ने कहा कि उन्होंने जीआईपी रेलवेमेन यूनियन ऑफ बॉम्बे का प्रतिनिधित्व करते हुए एआईटीयूसी के झरिया सत्र में भी भाग लिया था। यूनियन की सदस्यता 40 हजार से अधिक थी। 'साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग' प्रतिनिधि जेडब्ल्यू जॉनस्टोन को पंडाल से बाहर निकलते समय गिरफ्तार कर लिए गए। इसी सत्र में बेन ने मेरठ केस के आरोपी किशोरीलाल घोष, जो जूट और अन्य उद्योगों के श्रमिकों के नेता थे, के साथ अपनी दोस्ती को नवीनीकृत किया। बेन ने आंदोलन को आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश की, और 1928 में अखिल भारतीय डब्ल्यूपीपी सम्मेलन के लिए कलकत्ता की अपनी यात्रा पर कई श्रमिकों के क्षेत्रों का दौरा किया। वह जवाहरलाल नेहरू, बंकिम मुखर्जी और आयन किशोरी लाल के साथ बौरिया गए, हड़ताली श्रमिकों के आवासों का दौरा किया और आगे बढ़े। उनकी बैठकों को संबोधित किया। ब्रैडली ने फरवरी 1930 में जीआईपी रेलवे कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी सक्रिय भाग लिया।

वह उस समय संघ के उपाध्यक्ष थे।

ब्रैडली ने अपने बयान में जीकेयू के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए। उन्होंने बंबई की 1928 की प्रसिद्ध जीकेयू हड़ताल की उत्पत्ति और समस्याओं का पता लगाया। 18 अप्रैल 1928 को मजदूरों का एक जुलूस निकाला गया, जिसका समापन नागुसायाजी वाडा (चॉल) में एक बैठक के रूप में हुआ, जिसमें ब्रैडली ने भी भाषण दिया। एक हड़ताल समिति का गठन किया गया। जुलूस में लगभग 15,000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 26 अप्रैल तक बंबई की सभी मिलें बंद हो गई और मजदूर हड़ताल पर चले गए। बेन हड़ताल समिति के कोषाध्यक्षों में से एक थे।

जीकेयू की स्थापना 22 मई 1928 को नागु सयाजी वाडा में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में की गई थी और इस बार बेन को उपाध्यक्ष चुना गया था।

ब्रेडली को नवंबर 1933 में रिहा कर दिया गया और दो महीने के बाद वह ब्रिटेन लौट आए। लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर पहले सीपीजीबी सांसद शापुरजी सकलटवाला ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मेरठ कैदी रक्षा कोष की स्थापना की थी।

मेरठ जेल से अपने भाई ब्रैडली के साथ बेन का पत्राचार जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है।

पी.सी. जोशी और दत्त–ब्रैडली थीसिस, 1936

ब्रिटेन लौटने पर ब्रैडली विशेष रूप से औपनिवेशिक प्रश्नों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए जो भारत से सम्बंधित थे। समय था जब उपनिवेशवाद–विरोधी, साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष जोरों पर था। साथ ही, सैद्धांतिक, संगठनात्मक समस्याएं भी थीं, जिनसे ब्रैडली काफी परिचित थे। उनका अनुभव बहुत मददगार था।

कमिन्टर्न की छठी कांग्रेस ने 1928 में एक अत्यधिक संकीर्ण कार्यक्रम अपनाया था, जिसने कई साथियों और पार्टियों को काफी समय तक गुमराह किया गया था। सीपीआई के भीतर भी असमंजस की स्थिति थी. छठी कॉमिन्टर्न कांग्रेस ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग 'साम्राज्यवाद की ओर चला गया है' और यह कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से मिली हुई एक प्रतिक्रियावादी पार्टी थी। यह पंक्ति 1925 में पूर्व विश्वविद्यालय में लेनिन की स्थिति के विपरीत, स्टालिन के भाषण की अगली कड़ी थी। मेरठ काल के दौरान जेल से बाहर बीटी रणदिवे, वीडी देशपांडे और अन्य जैसे अपरिपक्व कामरेडों ने अपनी अत्यंत संकीर्ण लाइन को व्यवहार में लाया, जिसके परिणामस्वरूप आंदोलन में फॅट पड़ी।

मेरठ के कैदियों की रिहाई के बाद, सीपीआई ने फिर से संगठित होना होना शुरू कर दिया। दिसंबर 1933 में एक अंतरिम केंद्रीय समिति का गठन किया गया। इसके बाद यथार्थवादी समझ को अपनाने में मदद करते हुए, 1935 में पीसी जोशी को महासचिव चुना गया।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ने साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे की स्थापना और विस्तार की मांग की। यूरोप और एशिया में फासीवाद और नाजीवाद बढ़ रहे थे। विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष और एक व्यापक संयुक्त मोर्चे के लिए खुद को फिर से उन्मुख कर रहा था। कॉमिन्टर्न के महासचिव जॉर्जी दिमित्रोव की साम्राज्यवाद–विरोधी, फासीवाद–विरोधी संयुक्त मोर्चे पर रिपोर्ट ने एक नई दिशा प्रदान की।

इस बीच, चीन, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टियों के के पत्रों से सीपीआई को काफी मदद मिली।

बेन ब्रैडली स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर गांधीजी और कांग्रेस के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखते रहे थे। लेकिन वह धीरे–धीरे विकसित हुए और उन्होंने अपने विचारों को स्वस्थ और संतुलित दिशाओं में बदल दिया। दत्त–ब्रैडली थीसिस इसी परिवर्तन का प्रतिबिंब थे।

साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे के गठन पर आरपी दत्त और बेन ब्रैडली का पत्र 1936 में सीपीआई को प्राप्त हुआ था। यह 29 फरवरी 1936 को कॉमिन्टर्न की पत्रिका द इनप्रेकोर (इंटरनेशनल प्रेस कॉरेस्पोंडेंस) में प्रकाशित हुआ था।

इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चे में कांग्रेस, सीएसपी (कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी) और अन्य साम्राज्यवाद विरोधी संगठनों को शामिल करने का सुझाव दिया।

दत्त–ब्रैडली थीसिस ने कहा: 'राष्ट्रीय कांग्रेस एक महान भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।'

शेष पेज 15 पर...

देश में खुशहाली लाने के लिए इंडिया की सरकार बनाना जरूरी है: डा. भालचंद कांगो

भाकपा के बैनर तले शनिवार को जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। जिसमें वापमंथी वक्ताओं ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताते हुए कटघरे में खड़ा किया। जिना मुख्यालय में जोरदार रैली निकालकर वामपंथियों ने लोगों को अपनी ताकत का एहसास भी कराया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डा. भालचन्द्र कांगो ने कहा कि 38 दलों का एनडीए गठबंधन पूरी तरह से नाकाम हो गया है। शांति और कानून व्यवस्था नष्ट हो गई है। देश के अंदर मेहनत कर किसान मजदूर महिलाएं मध्यमवर्ग महंगाई से पीड़ित है। नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। रोजगार के साधन समाप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए सरकार हटाना ही एकमात्र विकल्प है। भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य डा. गिरीश ने कहा कि देश में जनता सरकार की नीतियों से परेशान होकर धरना प्रदर्शन कर रही, लेकिन भाजपा सांप्रदायिक आधार पर की विभाजन की राजनीति कर रही है। इंडिया गठबंधन में वामपंथी के शामिल होने के बावजूद कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने आवश्यकता है। मजदूर किसान व मेहनत कर जनता की आवाज उठाने के लिए वामपंथी की सशक्त जिम्मेदारी की आवश्यकता है। जनचेतना रैली को ऊर्जा देने के लिए जनता दल लोकतांत्रिक के नेता जुबेर अहमद ने कहा कि देश में कमजोर लोगों को सरकार के इशारों पर परेशान किया जा रहा है तथा उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे में धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एकजुटता के साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया के साथ तैयार हैं। जन चेतना रैली के प्रमुख आयोजक अमित यादव ने कहा कि एनडीए सरकार ध्वराकरईडी, सीबीआई सहित सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान करना चाहती है। जनचेतना रैली को पार्टी के सचिव मंडल सदस्य इम्तियाज अहमद, डा. रामचंद्र सरस, काति मिश्रा, श्यामसुंदर राजपूत, चंद्रपाल पाल, शालिनी पटेल, राष्ट्रीय परिषद सदस्य मोतीलाल, शिरोमणि सिंह राजपूत, रणधीर सिंह, सुमन, जमाल आलम मंसूरी आदि प्रमुख वक्ताओं ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता पूर्व विधायक राम प्रसाद सिंह ने किया। इसके पूर्व भारी हुजूम के साथ वामपंथियों ने जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय में अपनी ताकत का एहसास कराया।

आम चुनावों में जनता करेगी कारपोरेट हटाओ, भाजपा भगाओ

जौनपुर 9 अगस्त 2023: भारत छोड़ो आन्दोलन के दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा), रिवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी, सीपीआई–एमएल और संयुक्त किसान मोर्चा ने सम्मिलित रूप से कारपोरेट भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया। सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट परिसर में विकास भवन के सामने स्थापित क्रांति स्तम्भ पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पण का कार्यक्रम हुआ उसके बाद सभी साथी जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में धरनास्थल पर गये और जनसभा की।

धरना सभा का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के महामंत्री फूल चंद यादव ने कहा कि आज के दिन महात्मा गाँधी ने भारत छोड़ो आन्दोलन का उदघोष किया था। और गांधीजी के आह्वान का ऐसा असर हुआ कि देश भर में किसान, खेत मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी सभी ने पूरे जोश खरोश के साथ ऐसा तीव्र आन्दोलन चलाया कि अंग्रेजी सरकार की नीन्द हराम हो गई और अंग्रेजी राज को भारत को आजाद करने की मजबूरी दिखाई दी। अन्ततः उन्हें जाना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि जब देश आजादी की जंग लड़ रहा था तो सावरकर और गोलवलकर संघ और हिन्दू महासभा के लोग देश में घूम घूम कर अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का आवाहन कर रहे थे और आजादी का विरोध कर रहे थे, दुर्भाग्य से आज वही लोग जनता की आंख में धूल झोककर सत्ता पर काबिज हैं। हक और इन्साफ की आवाज उठाने वालों को देशद्रोही कह कर प्रताड़ित कर रहे हैं।

फूल चंद यादव ने याद दिलाया कि आज के ही दिन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में अंग्रेजी राज का खजाना लूट लिया था।

धरनासभा को सम्बोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य कल्पनाथ गुप्त ने कहा कि हम कहते हैं कि कारपोरेट भारत छोड़ो जिससे किसान मजदूर और आम आदमी अमन चैन से जी सकें, सुखी रह सकें। पर मोदी जी फर्जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। इनका मकसद है सभी भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाओ, यहाँ आने पर ईडी सीबीआई के भय से मुक्त हो जाओ। लेकिन कर्नाटक की तरह 2024 में जनता भाजपा भगाओ करेगी। इसी के साथ भाजपा के दलाल पूंजीपतियों का भी हिसाब करेगी।

नौजवान नेता ऊदल यादव ने कहा कि बेरोजगारी से परेशान नौजवान आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। यह गलत भी है शर्मनाक भी है। रोजगार मागना आज कल अपराध हो गया है। मोदी के हिसाब से मंहगाई और बेरोजगारी का सवाल करना देशद्रोह है ऐसा करने वाले देशद्रोही है। हमें क्रांतिकारियों के बताये रास्ते पर चल कर ही अपना और देश का भला करना है।

वरिष्ठ साथी रामप्रताप त्रिपाठी ने कहा कि आज आधा उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त और आधा उत्तर प्रदेश बाढ़ ग्रस्त और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांवड़ियों पर फूल बरसाने मे मस्त है। व्यापारियों को किसानों की लूट की छूट मिली हुई है। जो टमाटर किसानों को दाम के अभाव में सड़क पर फेंकना पड़ा था वही टमाटर भण्डारण करके 250 रू. किलो बिक रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार किसानों मजदूरों की हत्यारी है। धरना सभा को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री शालिग्राम पटेल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री राजदेव पटेल, आरएसपी के जिला मंत्री विजय प्रताप सिंह और संयुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजदेव यादव आदि ने सम्बोधित किया।

हिंसा की संक्रामक प्रक्रिया को रोकने में हो सकती है डाक्टरों की भूमिका

सामाजिक विकृतियां ही हैं उनकी जड़ें, उन पर कुठाराघात आवश्यक

डॉ. अरुण मित्रा

देश के कई हिस्सों में हाल की घटनाओं ने भारतीय समाज के समझदार तत्वों की चेतना को झकझोर कर रख दिया है। आजादी के समय शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था, गरीबी चरम पर थी, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मात्र 2.7 लाख करोड़ था वह भी 34 करोड़ की आबादी के लिए, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 3 प्रतिशत ही था। उस समय भी भारत के लोगों ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर आधारित संविधान को अपनाने का विकल्प चुना। यह इसके बावजूद था कि विभाजन के समय बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे और दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा जनसंख्या विस्थापन हुआ था।

इन घटनाओं ने भी सौहार्दपूर्ण समाज के लिए लोगों के निर्णय को नहीं रोका। बीच की कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो देश के लोग तब से एक–दूसरे के प्रति बिना किसी नफरत के एक साथ रहते आ रहे हैं। अब, जब हम सभी क्षेत्रों में विकसित हो गये हैं और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा कर रहे हैं, तो हमारे लोगों का एक वर्ग सांप्रदायिक आधार पर और दूसरों के खिलाफ नफरत से भर गया है और उनके मन में पूर्वाग्रह पैदा हो गया है।

समाज के एक वर्ग द्वारा विकसित की गयी यह मानसिकता मानवतावाद की उस अवधारणा के खिलाफ है जिसके लिए भारत हमेशा खड़ा रहा है। जनता को कट्टरता, झूठे प्रचार और मनगढ़ंत इतिहास से बहकाया जा रहा है। जाति, धर्म, जनजाति, और जातीयता के आधार पर दूसरों के प्रति नफरत के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की हानि होती है।

इतिहास में दर्ज है कि भारत के विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों में 25 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। वे हिंदू, सिख और मुस्लिम तीनों समुदायों के थे। नफरत अविश्वास को जन्म देती है जो आगे चलकर एक–दूसरे के खिलाफ हिंसा में तब्दील हो जाती है। हमने इसे 1984 में सिख विरोधी तथा 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी नरसंहार के दौरान देखा था।

ऐसी ही स्थिति कश्मीर में भी विकसित हुई जब अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को आतंकवादी खतरे और राज्य सरकार के रवैये के तहत पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए भारत में इस समय जो कुछ हो रहा है, वह कोई नयी घटना नहीं है, बल्कि अतीत में ऐसी ताकतें जो करने की कोशिश करती रही हैं, उसका ही एक सिलसिला है। जिन अल्पसंख्यकों को हिंदुओं की बहुसंख्यक 80 फीसदी आबादी के लिए खतरा माना जा रहा है, उनके खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। मुसलमानों के तुष्टिकरण जैसे मिथक लोगों के दिमाग में घर कर गये हैं और यह भी कि वे मशरूम की तरह उगेंगे और चार पत्नियों से शादी करेंगे और जल्द ही हिंदू आबादी से आगे निकल जायेंगे। इस घृणा अभियान में तर्क या सबूत का अभाव है। ये बेतुके विचार इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और कानाफूसी अभियानों के माध्यम से फैलाये जाते हैं। ऐतिहासिक धारावाहिक कहे जाने वाले कई टीवी धारावाहिकों का इस्तेमाल बहुत ही सूक्ष्म तरीके से झूठ और नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है।

ऐसी स्थितियों में महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। स्त्री के शरीर को संघर्षो में एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मणिपुर की घटना, जहां महिलाओं को नग्न घुमाया गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गयी, को घृणा, क्रोध और हमारी सामाजिक व्यवस्था में गंभीर विचलन के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए।

स्थिति के प्रति राज्य की पूरी असंवेदनशीलता इस बात पर संदेह पैदा करती है कि क्या इन घटनाओं को राज्य के संरक्षण में किसी गुप्त उद्देश्य के साथ अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया गया है। घृणा अभियान अपने आप नहीं रुकते।

अब हरियाणा में साम्प्रदायिक दंगे कराये गये हैं। नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं जबकि पीड़ितों पर अत्याचार किया जा रहा है। यूपी, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं। अगर अभी इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इससे गुजरात या मणिपुर के स्तर की बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है।

जो ताकतें इस तरह के नफरत भरे अभियान चलाती हैं, वे हमेशा यह प्रयास करती रहती हैं कि वे कैसे जनता को अपने पक्ष में कर सकें। 1995 में देशभर में भगवान गणेश की दूध पीती प्रतिमा की घटना बेहद सफल परीक्षण थी। यह संदेश कुछ ही समय में पूरे देश में फैल गया, जबकि उस समय कोई सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं था। जब लगा कि पूरा मिथक उजागर हो जायेगा तो यह तुरंत रुक गया। गौरतलब है कि इसके बाद गुजरात में हिंसा हुई थी। यह आश्चर्यजनक है कि महात्मा गांधी की भूमि पर ऐसी अभूतपूर्व हिंसा हुई।

ऐसी स्थितियों पर काबू पाने में डॉक्टर सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। समाज के स्वास्थ्य के संरक्षक के रूप में डॉक्टरों का कर्तव्य है कि वे अपनी बात कहें और उचित निर्णय लें। उन्हें आगे आना होगा और सद्भाव, प्रेम, और भाईचारे का प्रचार करने के लिए सम्पर्क कार्यक्रम बनाने होंगे। ऐसी स्थितियों में पीड़ित लोगों में आत्मविश्वास विकसित करने में डॉक्टर एक बड़ा साधन हो सकते हैं।

विक्टर फ्रेंकल, एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक, जो नरसंहार से बचे थे, ने नाजी एकाग्रता शिविरों में कैदियों को बेहतर भविष्य की आशा कभी नहीं खोने के लिए प्रेरित करने का एक महान काम किया। अपने लगातार प्रयासों से उसने हिटलर के युद्ध हारने के बाद कई लोगों को मरने से बचाने और जीवित रहने में सक्षम बनाया था।

हमारी आवाज मायने रखती है। लेकिन हमारी चुप्पी पेचीदा और कर्तव्य के प्रति लापरवाही हो सकती है। नफरत फैलाने वालों की लगातार धमकियों और राज्य की संदिग्ध भूमिका के बावजूद बदलाव आ रहा है। कई वैज्ञानिक जो अब तक शांत थे, मिथकों और अवैज्ञानिक विचारों को चुनौती देने लगे हैं। ताली और थाली बजाने वाले डॉक्टरों को अब एहसास हो गया है कि यह कोविड से छुटकारा पाने का वैज्ञानिक तरीका नहीं था। अंततः हमें 1600 डॉक्टरों की जान की कीमत पर महामारी से लड़ना पड़ा। गौमूत्र या गोबर अभियान का कोई भी अभियान काम नहीं आया।

कई डॉक्टर इस बात को समझते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उन्हें बोलने की हिम्मत जुटानी चाहिए। घृणा अभियानों का राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर मुकाबला किया जाना चाहिए। डॉक्टरों को चुप नहीं बैठना है बल्कि देश को इस संकट से बाहर निकालने के उपाय खोजने हैं। डॉक्टर अपने मरीजों के साथ संवाद कर सकते हैं और नरम स्वर में प्यार और करुणा की बात कर सकते हैं जो हमारे पेशे का एक हिस्सा है।

फिर उनसे उनकी भाषा में बात करें। हमें उन ताकतों की पहचान करने से नहीं कतराना चाहिए जो सौहार्द बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि इस तरह की हिंसा एक महामारी स्वास्थ्य समस्या है और इस प्रकार योजना बनायें जैसे हम अन्य बीमारियों के लिए करते हैं। प्राथमिक रोकथाम दृष्टिकोण स्थिति को खराब होने से रोकना है और हिंसा शुरू होने से पहले हिंसा को रोकना है। द्वितीयक रोकथाम जोखिम वाली आबादी और अंतर्निहित जोखिम कारकों को लक्षित करना है।

सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि हिंसक व्यवहार संक्रामक प्रक्रिया है और इससे समान तरीके से निपटना होगा। प्रेम, सहानुभूति, और दूसरों की देखभाल पर जोर देकर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। फैलाये जा रहे झूठ को बेनकाब करें। तर्क और प्रमाण पर बात करें। कमजोरों और वंचितों के प्रति विनम्र रहें और हमारे समाज में उन हाशिए पर रहने वाले लोगों के खिलाफ दृढ़ रहें जो हमारे देश में सामाजिक सद्भाव के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

समय आ गया है कि हम चुप्पी तोड़ें।

गलत के सामने कभी बगलें न झांकें। (संवाद)

पटना में भाजपा हटाओ, देश बचाओ रैली की तैयारी जोरों पर

मधुबनी, 10 अगस्त 2023: बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन मधुबनी जिला परिषद की विस्तारित बैठक गुरुवार को शहीद भवन भाकपा कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामनारायण यादव ने की। बैठक को भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय, पार्टी के जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा, यूनियन के जिला सचिव रामचन्द्र पासवान, महिला नेत्री राजश्री किरण, कृपानंद आजाद, लक्ष्मण चौधरी, राकेश कुमार पांडेय, यमुना पासवान, मनोज कुमार मिश्र, सूर्यनारायण यादव, सूर्यनारायण महतो, बालकृष्ण मंडल, किरणेश कुमार, रामपुकार मुखिया आदि ने संबोधित किया। बैठक में दो नबम्बर 2023 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित भाजपा हटाओ, देश बचाओ रैली और दो से पांच नवम्बर तक आयोजित भारतीय खेत मजदूर यूनियन के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन पर विस्तार से चर्चा की। भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने दो नवम्बर की पटना रैली की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। रैली में मधुबनी से तीस हजार से अधिक पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षो के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हमले खेत मजदूरों पर हुए हैं। डबल इंजन की सरकार में मणिपुर और हरियाणा जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं। प्रधानमंत्री संसद नहीं आ रहे हैं। मजदूरों को रोजगार नहीं मिला रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की राशि में लगातार कटौती की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को बंद करने की साजिश की जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। खाद्य वस्तुओं की कीमत में लगातार बढोतरी हो रही है। खेत मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य नहीं मिल रहा है। मनरेगा मजदूरों को वाजिब मजदूरी नहीं मिल रही है। मनरेगा की मजदूरी प्रत्येक दिन कम से कम 600 रुपये की जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रत्येक महीने पांच हजार रुपये की जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खेत मजदूरों के सवालों को लेकर आंदोलन तेज करेगी।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सभी मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुई है। यह सरकार गरीब विरोधी और पूंजीपतियों की हितैषी है। गरीब हितैषी कल्याणकारी योजनाओं की राशि में कटौती की जा रही है तो पूंजीपतियों के 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता जाने का डर सताने लगा है। इसी बौखलाहट में प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की हार तय हो गई है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया की जीत होगी।

कुछ सामयिक मुद्दे और घटनाक्रम

आर.एस. यादव

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में

2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की कार्य करने की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निष्पक्षता का क्षरण होता रहा है और संवैधानिक संस्थाएं, जिन्हें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिएं, सरकार के इशारे पर और सरकार के पक्ष में फैसले लेती देखी गई हैं। केंद्र सरकार ने अब 10 अगस्त 2023 को राज्य सभा में एक बिल पेश किया है: मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, शर्तें और पद अवधि) विधेयक, 2023। यदि यह बिल पारित हो गया तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता पर ही प्रश्न लग जाएगा और आयोग सरकार का एक वफादार नौकर बन कर रह जाएगा।

यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2023 में दिए गए उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद की ओर से कानून न बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायधीश की सदस्यता वाली समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी।

न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि यह मानक तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता।

आदेश पारित करते समय पीठ ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कोई संसदीय कानून नहीं है, इसलिए कोर्ट का आदेश संवैधानिक शून्यता को भरने के लिए है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि ''एक चुनाव आयोग जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं करता है, वह कानून के शासन की नींव के टूटने की गारंटी देता है''।

राज्य सभा में पेश बिल के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्र के एक केबिनेट मंत्री शमिल होंगे। विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का स्टेटस भी घटा दिया गया है। अभी तक उनका स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है और उन्हें वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दिया जाता है। परंतु विधेयक के अनुसार, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का वेतन और भत्ते अब केबिनेट सचिव के बराबर होंगे। संसद में विधेयक पारित होने के बार वरीयता क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को राज्य मंत्री से नीचे का दर्जा दिया जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इस बिल में प्रस्तावित समिति में प्रधानमंत्री और उन द्वारा नामित एक केबिनेट मंत्री, दोनों मिलकर बहुमत बन जाते हैं और समिति में विपक्ष के नेता की कोई भूमिका ही नहीं रह जाएगी। जाहिर है समिति के इस गठन में यह निहित है कि प्रधानमंत्री जिसे चाहेंगे उसे मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बना सकते हैं।

यह बिल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जस्टिस जोसफ वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ की भावना से स्पष्टत: विपरीत है। यह बिल चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के स्थान पर उसे प्रधानमंत्री के हाथों की एक कठपुतली बनाने की कोशिश है। इससे चुनाव आयोग सरकार का आज्ञाकारी और वफादार नौकर बनकर रह जाएगा।

देश में चुनाव कराने का काम भारत का चुनाव आयोग करता है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण चुनाव आयोग को सौंपा गया है। चुनाव आयोग सरकार का आज्ञाकारी और वफादार नौकर बन गया तो समझिए भारत में लोकतंत्र के ध्वस्तीकरण की शुरूआत हो गई।

2024 में लोकसभा के चुनावों से ठीक पहले इस तरह के बिल के लाए जाने से सरकार के बदनीयत इरादे का इशारा मिलता है।

महंगाई

15 अगस्त 2023 को जिस दिन प्रधानमंत्री लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए देशवासियों की वास्तविक समस्याओं से रू–ब–रू न होकर आत्मप्रशंसा में लगे थे उसी दिन के समाचार पत्रों में पहले पृष्ठ की खबर थी कि महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है और उनका घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। प्रधानमंत्री के भाषण में न महंगाई का जिक्र था और न बेरोजगारी का जो देश की सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं।

14 अगस्त को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जुलाई 2023 में बढ़कर 7.44 प्रतिशत रही जो पिछले 15 महीनों में सबसे अधिक महंगाई का आंकड़ा है।

प्रसार भारती के अनुसार, स्वाधीनता के मौके पर लालकिले से प्रधानमंत्री के भाषण के लिए लालकिला परिसर में 36 कैमरों से उनके संबोधन के प्रसारण की व्यवस्था की गई। उनके भाषण का प्रसारण 36 कैमरों से किया जाए या दस हजार कैमरों से किया जाए, क्या उससे महंगाई की समस्या कम हो सकती है, क्या उससे बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिल सकता है?

बीते वर्ष में अधिकतर समय खुदरा महंगाई की दर 6 प्रतिशत से ऊपर रही है जिसे रिजर्व बैंक द्वारा महंगाई का सहनसीमा स्तर माना जाता है। पिछले साल जुलाई में भी महंगाई 6.6 प्रतिशत थी। सालाना आधार पर सब्जियों की महंगाई दर जुलाई 2023 में 37.44 प्रतिशत, मसालों में 21.63 प्रतिशत, दाल में 13.27 प्रतिशत, और अनाज एवं उसके उत्पादों की महंगाई दर 13 प्रतिशत रही। महंगाई दर का यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है जिसे यथासंभव कम कर बताया जाता है। लोग जिस महंगाई का सामना कर रहे हैं, वह वास्तविक महंगाई इस सरकारी आंकड़े से कहीं अधिक है। देश के आदमी की आमदनी में वृद्धि नहीं हो रही है जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आम आदमी कैसे गुजारा करता है, वही जानता है।

नफरती भाषणों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश

सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश कर चुका है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, पुलिस तंत्र एवं अन्य प्रशासनिक तंत्र को नफरती भाषणों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए और इस तर के भाषणों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

हरियाणा में नूंह में पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर नफरती भाषणों पर नकेल लगाने को लेकर सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी रेखांकित की है। अदालत ने कहा कि ऐसे भाषणों और अपराधों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाया जाए। अदालत ने कहा कि नफरत आधारित अपराध और नफरती बयान पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। लगभग एक वर्ष पपहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को नफरती भाषणों पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की थी।

अब अदालत ने फिर कहा है कि पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया जाएं कि वे एक ऐसी समिति बनाएं जो अलग–अलग इलाकों के थानाप्रभारियों से प्राप्त नफरती बयान संबंधी शिकायतों पर गौर करके उनकी सामग्री की जांच करें और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करे। दिल्ली दंगों, विधानसभा चुनावों के दौरान और फिर उत्तराखंड तथा देश के अन्य हिस्सों में आयोजित धर्मसंसदों में जब अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक बातें कही गई थी, तब भी न्यायालय ने पुलिस को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई थी।

प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट तक के इस तरह के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नफरती भाषण क्यों किए जाते हैं; तथाकथित धर्मसंसदों के नाम पर किए जाने वाले आयोजनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ उकसाने वाले भाषण और आह्वान क्यों किए जाते हैं; धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर ऐसे नए–नए आयोजनों/जुलूसों आदि की शुरूआत पिछले वर्षों में क्यों हुई है जो पहले नहीं हुआ करते थे और जिनमें खुलेआम हथियार लहराए जाते हैं, जिनके नारों में कोई धार्मिक तत्व होने के बजाय अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला जाता है और ऐसे आयोजनों को सरकार का संरक्षण क्यों मिलता है? प्रश्न यह भी है कि तमाम नफरती भाषणों और धार्मिक जुलूसों के नाम पर अल्पसंख्यक विरोधी आयोजनों के पीछे कौन–सा प्रेरक तत्व है और कौन–सी प्रेरक शक्ति है?

क्या यह एक तथ्य नहीं है कि ये सब आयोजन उस पार्टी के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संरक्षण और प्रेरणा और इशारे पर किए जाते हैं जिसकी आज केंद्र में सरकार है? जब तथ्य यह है तो पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह नफरती भाषण करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी?

सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश करता रहे, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री और केंद्र के कोई मंत्री सांप्रदायिक उकसावापूर्ण भाषण करें तो पुलिस का कोई अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। इस संबंध में याद करना उचित होगा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस एस. मुरलीधर की पीठ ने पुलिस और सोलीसिटर जनरल की इस बात के लिए भर्त्सना की कि भाजपा नेताओं के खिलाफ भड़काने वाले–उकसाने वाले भाषणों के लिए मामले दर्ज क्यों नहीं किए गए, तो रातोंरात उनका तबादला हो गया था। इतना ही नहीं, जज के तौर पर उनके एक उदाहरणीय रिकॉर्ड और एक असाधारण कानूनी विद्वान के तौर पर उनकी पहचान होने के बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। यह एक असाधारण बात है कि एक संवैधानिक विधिवेत्ता और सुप्रीम कोर्ट के जानेमाने सीनियर एडवोकेट फाली नरीमन, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी. लोकुर और सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ एडवोकेट श्रीराम पांचू ने सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जस्टिस एस. मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर लाने से क्यों इनकार किया? किस आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के उनके न्यायसंगत अधिकार से वंचित किया गया? (संदर्भ, द इंडियन एक्सप्रेस (16 अगस्त 2023) में नरीमन, लोकुर एवं पांचू का लेख, ''ए क्वेशचन फॉर सुप्रीम कोर्ट)

इन हालात में नफरती भाषणों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के बार–बार आदेश के बावजूद, नफरती भाषणों के खिलाफ गंभीरता से कोई कार्रवाई न की जाने के कारण को समझा जा सकता है।

क्या हम नहीं जानते कि सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर चुनावी फसल काटना, यही भाजपा की चुनावी रणनीति का मुख्य पहलू है? और यहीं से नफरती भाषणों का खेल शुरू होता है।

समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया केरल विधान सभा ने

8 अगस्त 2023 को केरल विधान सभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जिससे यह राज्य इस तरह का प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा पेश प्रस्ताव को विधान सभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केंद्र सरकार का एकतरफा और जल्दबाजी वाला कदम संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म कर रहा है। केंद्र सरकार बिना किसी वैचारिक बहस में शामिल हुए या सर्वसम्मति की तलाश किए बिना इस एकतरफा कदम की दिशा में आगे बढ़ रही है।

प्रस्ताव में मांग की गई कि केंद्र सरकार देश की पूरी आबादी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर इस तरह के कदम उठाने से बचे। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे आबादी के विभिन्न वर्गों में चिंता पैदा हो रही है। यह चिंता केरल विधान सभा द्वारा साझा की गई है। यह रेखांकित करता है कि एकल नागरिक संहिता एक विभाजनकारी कदम है जो लोगों की एकता को खतरे में डालता है और राष्ट्र की एकजुटता के लिए हानिकारक है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्र संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करता है।

शेष पेज 15 पर...

गुज्जुला येल्लामंडा रेड्डी जन्मशती समारोह का उद्घाटन

चुनाव सुधार और समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की जरूरत

राम नरसिम्हा राव

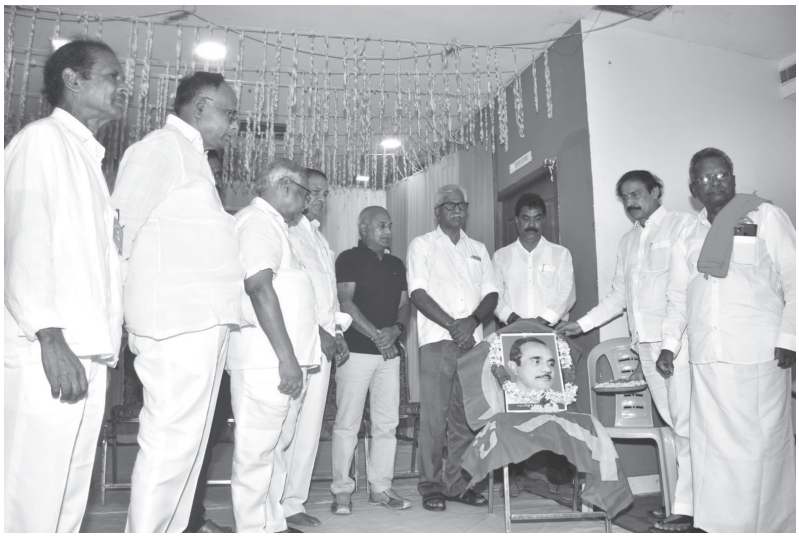

भारतीय खेत मजदूर यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गुज्जुला येल्लामंडा रेड्डी की जन्मशती समारोह का उद्घाटन, 13 अगस्त 2023 को भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य, राज्य सभा सांसद बिनोय विश्वम ने आंध्रप्रदेश के तटीयवर्ती जिले प्रकाशम के ओंगोल शहर स्थिति बच्चाला बलैया कल्याण मंडपम में किया गया। स्वर्गीय गुज्जुला येल्लामंडा रेड्डी जन्मशती समारोह के उद्घाटन अवसर पर एक स्मृति व्याख्यान–भारतीय संसदीय जनतंत्र– चुनाव सुधार और समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की जरूरत'' आयोजित किया गया था।

उद्घाटन समारोह में भाकपा राज्य सचिव के रामाकृष्णा, बीकेएमयू के राष्ट्रीय सचिव ए. राममूर्ति, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक परकल्ला प्रभाकर, पूर्व एमएलसी जल्ली विल्सन एवं पी. जे. चन्द्रशेखर, भाकपा राज्य सचिवमंडल सदस्य गुज्जुला इश्वरैया, बीकेएमयू के राज्य सचिव अवुला ईश्वर मौजूद थे।

गुज्जुला येल्लामंडा रेड्डी स्मृति व्याख्यान में बिनोय विश्वम ने अपने व्याख्यान में कहा कि ''भाजपा सरकार हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के नष्ट कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्पोरेट मालिकों के हितों की सेवा कर रहे हैं, मोदी सरकार ने भारतीय जनतंत्र को कुछ कॉर्पोरेट ताकतों को सौंप दिया है। यह शर्मनाक है कि भाजपा और आरएसएस ने स्वाधीनता सग्राम में हिस्सा नहीं लिया था और अब स्वयं को देशभक्त कह रहे हैं। आरएसएस जिसने दिन–रात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों के लिए काम किया, लेकिन शस्त्र संघर्ष के अग्रजों के रूप में स्वयं की शेखी बघारते हैं। बिनोय विश्वम ने जोर देते हुए कहा कि समय की जरूरत है चुनावी सुधार खासकर समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति।

मौजूदा चुनावी व्यवस्था कॉर्पोरेट ताकतों की पकड़ में है। प्रत्याशी उम्मीदवार हजारों करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च कर रहे हैं। अडानी, अंबानी समेत कई कॉर्पोरेट घराने सत्ताधारी दलों को चंदे के रूप में विशाल धनराशि दे रहे हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के माध्यम से चुनाव व्यवस्था में सुधार से समाज में बदलाव आ सकता है। आम व्यक्तियों के संसद एवं अन्य विधायी निकायों में पहुंचने से उत्पीड़नों, हमलों, भ्रष्टाचार,

अनियमितताओं, हत्याओं आदि पर रोक लगेगी। बिनोय विश्वम ने कहा कि गुज्जुला येल्लामंडा से प्रेरणा लेते हुए नेताओं को जनता को जागृत करने के लिए आगे बढ़ना होगा।

लेखक और राजनीति विश्लेषक परकल्ला प्रभाकर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत को ऐसी संसदीय व्यवस्था की जरूरत है जिसमें बहस हो सके। संसद में बिना चर्चा तीन कृषि कानूनों का पास होना क्या यह चिंता का विषय नहीं है? और कैसे ये तीनों कानून बगैर किसी चर्चा के वापिस ले लिए गए? हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है।

भाजपा सरकार मात्र 38 प्रतिशत मतों से सत्ता में आई है और आम लोगों की जिन्दगी से खेल रही है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से नष्ट कर दिया गया। यह खतरनाक संकेत है कि इस देश के लोग और पार्टियां मणिपुर, गुजरात और बिहार की घटनाओं पर निष्क्रिय हैं। जनता को सीखना होगा सरकार की जनविरोधी नीतियों पर सवाल उठाना।

जब केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट कंपनियों का लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जब लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया और खामोश रहे जबकि सरकार ने आम आदमियों पर कर का बोझ 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया और वहीं कॉर्पोरेट कंपनियों के 23 प्रतिशत कर को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया तब लोगों का विद्रोह न करना एक खतरनाक संकेत है। केंद्र सरकार की राज्य की शक्तियों को छीनना जनतंत्र के ह्रास के अलावा ओर कुछ नहीं है।

भाकपा आंध्रप्रदेश राज्य सचिव के रामकृष्णा ने अपने भाषण में कहा कि मोदी के सत्ता में आने से पहले भारत पर कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ रुपये था और मात्र दस सालों में यह कर्ज बढ़कर हजार लाख करोड़ रुपये हो गया है। आरएसएस के इशारों पर भाजपा सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है और दंगे कर रही है। उत्तरप्रदेश में अल्पसंख्यकों की 18 प्रतिशत आबादी के बावजूद भाजपा का उत्तर प्रदेश से कोई सांसद या विधायक मुसलमान नहीं है। यह भाजपा की मुसलमान से नफरत का स्पष्ट संकेत है।

जगनमोहन रेड्डी के सत्ता में आने के बाद से राज्य का विकास दस साल पीछे पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरूद्ध जन अभियान के रूप में भाकपा बस यात्रा 17 अगस्त 2023 से शुरू करेगी। यह यात्रा वाइजेग स्टील प्लांट के गेट से शुरू होगी और इसका समापन तिरुपति में एक बड़ी जन सभा से होगा।

अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावुला वैंकेया ने स्मृति व्याख्यान में येल्लामंडा रेड्डी के साथ काम करने के 50 सालों का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि येल्लामंडा रेड्डी ने कृषि मजदूरों के कई आंदोलनों को शुरू किया। वे सांसद चुने गए और तीन बार विधायक चुने गए लेकिन उन्होंने अपना स्वयं का घर नहीं बनाया था।

गुज्जुला इश्वरैया ने बताया कि येल्लमंडा रेड्डी ने वाइजेग स्टील प्लांट के लिए आंदोलन में अपने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था।

प्रखंड कार्यालय पर मांगों के लिए खेत मजदूरों का प्रदर्शन

मकेर (सारण) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं खेत मजदूर यूनियन की प्रखंड इकाई की ओर से 9 सूत्री मांगों के समर्थन में मकेर प्रखंड कार्यालय पर रोस पूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झंडा बैनर एवं मांगों के लिए नारे लगाते हुए अमनौर मकेर बाजार में जुलूस की शक्ल में प्रखंड कार्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। जुलूस का नेतृत्व भाकपा जिला प्रभारी सचिव रामबाबू सिंह, अंचल सचिव मोहन राय, सहायक सुरेंद्र राम, यूनियन अध्यक्ष महात्मा कुमार रवि, सचिव दीपक दास एवं कोषाध्यक्ष भूषण नट कर रहे थे।

मांगो में कस्बा मकेर पंचायत के कस्बा मकेर अंजनी सहित तमाम ग्रामों के गरीबों को आवासीय भूमि मुहैया करने, सबों को राशन कार्ड देने, दलित बस्तियों में सरकारी विद्यालय खोलने, सामुदायिक शौचालय का इंतजाम करने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का दुगना करने एवं जिन्हें नहीं मिलता है उन्हें पेंशन देने, जल निकासी का समुचित इंतजाम करने दलित बस्तियों का मुख्य सड़क से जोड़ने मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी करने एवं 600 रू. प्रति कार्य दिन मजदूरी देने की मांगे शामिल है। प्रदर्शन के उपरांत बीडीओ को मांग पत्र भेंट किया गया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव रामबाबू सिंह ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उसे अविलंब पूरा करने की मांग की अन्यथा तीव्र आंदोलन की चेतावनी प्रखंड प्रशासन को दी। साथ ही 2 नवंबर को पटना रैली को सफल बनाने का आह्वान भी किया। प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी काफी थी। जिसमें मनोरमा देवी, सीता देवी, कोशिला देवी, रूबना खातून, मैनू निशा, राजेश्वर सिंह, राम अयोध्या राय, मुन्ना सिंह, जगा सिंह, जयपाल सिंह आदि शामिल थे।

छात्र विरोधी आदेश के खिलाफ एआईएसएफ का प्रदर्शन, गिरफ्तारी

शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने की मांग को लेकर एआईएसएफ ने तेलंगाना राज्य सचिवालय का किया घेराव। एआईएसएफ तेलंगाना राज्य परिषद ने 10 अगस्त को छात्रों के विभिन्न मुद्दों की मांग को लेकर राज्य सचिवालय भवन मार्च का आयोजन किया। एआईएसएफ ने राज्य में सरकारी स्कूलों–कॉलेजों को बंद करने और निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने की निंदा की।

फीस प्रतिपूर्ति जैसी लंबे समय से लंबित मांगें, सरकारी एससी एसटी छात्रावासों में मेस में बढ़ोतरी की मांग भी एआईएसएफ ने की। राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि सरकारी छात्रावासों और सरकारी शिक्षा संस्थानों में छात्र संगठन के नेता, मीडिया या अन्य राजनीतिक दल प्रवेश नहीं करेंगे।

यह आदेश छात्रों को छात्र संगठनों के साथ अपनी समस्याएं व्यक्त करने से वंचित करता है। सरकार सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्र समुदाय की समस्याओं और तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है।

एआईएसएफ ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए अलोकतांत्रिक आदेश का कड़ा विरोध किया। एआईएसएफ ने ऐसे अलोकतांत्रिक आदेश के विरोध में तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन की घेराबंदी करने का आह्वान किया। एआईएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष मणिकांत रेड्डी, प्रदेश सचिव पुट्टा लक्ष्मण के नेतृत्व में रैली में शामिल छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और सैंकडों छात्रों को हिरासत में ले लिया गया।

मोदी गद्दी छोडो के नारे के साथ देशभर में मना अगस्त क्रान्ति दिवस

सोनभद्र (उप्र): अगस्त क्रांति दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग से जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पर पंहुच कर परिसर स्थित गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और घंटों धरना दिया। जहां जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अगस्त क्रांति जिंदाबाद, नफरत की राजनीति बंद करो और अंग्रेजों के पिट्ठू भाजपाई गद्दी छोड़ो के नारे लगाये गये।

गांधी जी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया और गांधी पार्क में धरना दिया गया।

वक्ताओं ने कहा कि भारत की जनता ने राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में भागीदारी करते हुए 9 अगस्त को 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' नारा दिया था। महात्मा गांधी के नारे 'करो या मरो' पर देश के नौजवान और जनता सड़क पर थे। देश आजाद हुआ देश के संविधान ने देश के लिए कुछ मूल्यों का निर्माण किया। आज दिल्ली में भी और लखनऊ में भी आरएसएस व भाजपा की ऐसी सरकार बैठी है जिसके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सेदारी नहीं की और ना ही संविधान में दर्ज मूल्यों का उनके लिए कोई महत्व रहा।

चूंकि देश का संविधान अभी है इसलिए उस संविधान को वह एक तरफा अचानक ही निरस्त नहीं कर सकते, परंतु पिछले 9 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकारें चल रही है और वह जो कार्य कर रही है उससे निरंतर संवैधानिक मूल्यों को तिरिस्कृत किया है और उनकी कोशिश है कि संवैधानिक मूल्यों से परे देश में एक हिंदुत्ववादी धार्मिक राज्य का अस्तित्व आ जाए।

देश की करोड़ों जनता उनकी इस कोशिश का विरोध कर रही है।

पिछले 9 सालों से देश बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिक वैमनस्यता से जूझ रहा है। अदानी, अंबानी जैसे पूंजीपतियों की चांदी है और देश की 40 करोड़ से अधिक जनता गरीब रहने को अभिशप्त है।

इन परिस्थितियों में भी देश की सरकार अथवा उससे जुड़े उसके अनुषांगिक संगठन देश में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने से चूक नहीं रहे हैं। हाल फिलहाल इतने उदाहरण सामने आ गए हैं कि ऐसा लगता है 2024 के पहले देश को बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक वैमनस्यता की ओर ले जाना चाहते हैं।

हरियाणा की घटनाएं, ट्रेन में सिपाही के द्वारा गोली चलाकर लोगों की हत्या करना अथवा पिछले 3 महीने से मणिपुर में मणिपुर की जनता को बांट कर उनका नरसंहार करना अथवा मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के द्वारा स्पष्ट रूप से अदालतों के फैसलों के विपरीत सांप्रदायिकता से भरे हुए बयान जारी करना इसके उदाहरण है। उदाहरणों की एक लिस्ट बन सकती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दल निरंतर लड़ रही है और आज ऐतिहासिक दिन अगस्त क्रांति दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी–सोनभद्र व उसके कार्यकर्ता जनता की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना दे रहे हैं। उपरोक्त समस्याओं के साथ साथ पार्टी द्वारा सात सुत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा गया जिसमें बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचना बंद कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए आदि मांगें शामिल थीं।

इस मौके पर प्रमुख रूप से भाकपा के जिला सचिव आर के शर्मा, लालता प्रसाद तिवारी, दूर्गा प्रसाद, बसावन गुप्ता, विजय भारती, अमरनाथ सूर्य, दिनेश्वर वर्मा, पप्पू भारती, कमलेश गोंड, सूरज धरकार, राम विलास कोल, राम लखन, गुलाब धांगर, अशोक कुमार कन्नौजिया, हीरावती देवी, मालती देवी, श्रीदेवी, फूलमती आदि पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम सागर जी ने और संचालन देव कुमार विश्वकर्मा जी ने किया।

गोरखपुर

श्रम कानूनों के कड़ाई से परिपालन, मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं की वापसी, न्यूनतम मजदूरी कम से कम 26000/– प्रतिमाह किये जाने, आंगनबाड़ी आशा, मनरेगा सहित सभी स्कीम कर्मियों को राज्यकर्मी घोषित करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, ईपीएफ पेंशन कम से कम 7000/– प्रतिमाह किये जाने, निगमों निकायों में वर्षों से आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, हड़ताल के कारण हटाए गए संविदा विद्युतकर्मियों की बहाली, कर्मचारी उत्पीड़न की समाप्ति, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं लागू किये जाने और श्रम वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये समयसीमा और आधारभूत संसाधन सुनिश्चित किये जाने सहित अन्य मांगों को लेकर केन्द्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त आह्वान पर क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों पर श्रमिक पड़ाव का निर्णय लिया गया है। ये पड़ाव आजादी के अगस्त क्रांति दिवस पर हुआ। तदोपरांत देश/प्रदेश के मुखिया को संबोधित प्रतिवेदन दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में श्रम कार्यालय के सामने इस श्रमिक पड़ाव के माध्यम से दिल्ली में आयोजित पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की रैली के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एचएमएस के अश्वनी पाण्डेय तथा संचालन एक्टू के राजेश साहनी ने किया। धरने को एटक के राममूर्ति ने संबोधित करते हुये कहा कि भाजपा केन्द्र व राज्य की मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी व जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध पूरे देश का मजदूर आंदोलन पर उतर गया है। यदि मजदूरों की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं करती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिये मजदूर वर्ग अभी से कमर कस लेगा।

धरने में सीटू के जावेद अजीज, एटक के रविशंकर सिंह, विद्युत मजदूर मोर्चा के संदीप श्रीवास्तव, समाचार पत्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष उमाशंकर मझवार, राजद नेता महेन्द्र सिंह राणा, गौतम लाल, डॉ. आशीष कुमार सिंह, मनोरमा चौहान, रामयश, हरिद्वार, एसके डे, राकेश श्रीवास्तव, डॉ. दीनानाथ भट्ट, नंदकिशोर मौर्य, अटल बिहारी सिंह, बृजेश मिश्रा महामंत्री एचएमएस आदि शामिल रहे।

रायपुर

देश की 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त नेतृत्व में 9 अगस्त 2023 को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी महापड़ाव का आयोजन किया गया था जिसके अंतर्गत बुढ़ा तालाब, रायपुर (छ.ग.) में भी 9 अगस्त 1942 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' की यादगार दिवस के अवसर पर 'मोदी गद्दी छोड़ो' के नारों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य एटक के विभिन्न जिलों के विभिन्न जन संगठनों से संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों छत्तीसगढ़ आटो चालक संघ एटक, छत्तीसगढ़ न्यू प्रगतिशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ एटक, छ. ग. मध्य भारत पेपर मिल श्रमिक संघ एटक, मड़वा ताप विद्युत कामगार एवं भू–विस्थापित श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़

शेष पेज 15 पर...

भाकपा और अन्य दलों का अडानी हटाओ, धारावी बचाओ आंदोलन

धारावी (मुम्बई), 9 अगस्त 2023: अडानी हटाओ, धारावी बचाओ आंदोलन के तहत अडानी चले जाओ सर्वपक्षीय जाहिर सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता शिव सेना के माजी आमदार बाबुराव माने ने की।

प्रमुख वक्ताओं में थे सपा महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबु आजमी, आरपीआई मुंबई अध्यक्ष सिद्दार्थ कसारे, भाकपा के मुंबई सचिव मिलिंद रनाडे, भाकपा के मुंबई सचिवमंडल सदस्य और धारावी बचाओ आंदोलन के प्रमुख समन्वक में से एक नसीरूल हक, सीपीआई (एम) के वसंत खंदारे, संगीता कंबले, शेकप के नेता राजेंद्र कोरडे, भाजपा के रमाकांत गुप्ता, आपीआई के मारन नगम मारी भाई और संजय भालेराव, शिव सेना धारावी विभाग प्रमुख विट्ठल पावर, शिव सेना के पूर्व नगर सेवक वसंत नक्काशे, समाजिक कार्यकर्ता सुरेश सावंत, शेकप नेता शामिया कोरडे, भाड़ेकरूँ महासंघ के अनिल कसारे, नितिन देवकर, आप के संदीप कटके, पाल राफेल के यूनुस खान आदि शामिल थे। सपा आमदार अबु आजमी ने कहा कि अडानी को धारावी का प्रोजेक्ट गलत ढंग से दिया गया है मकसद है धारावी के लोगों को उजाड़ कर बेदखल करने का यहां से अडानी को मुनाफा कमाना है। धारावी के लोगों को धारावी के उद्योग को उजड़ने से बचाना है तो लड़ना होगा, हम आजाद मैदान में बड़ा मोर्चा करेंगे। असेंबली में भी आवाज उठाएंगे।

भाकपा मुंबई सचिव मिलिंद रनाडे ने कहा कि अडानी कौन है मोदी के दोस्त हैं, वह कोई समान नहीं बनाता है, वह मकान कैसे बनाएगा। वह कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता वह श्रीमंत कैसे बना उस में मोदी का सहयोग है। नीरव मोदी, मेहूल चौकसी, ललित मोदी बैंक का कर्जा लेकर भाग गए, अगर अडानी धारावी के प्रोजेक्ट को दिखा कर 50 हजार करोड़ रुपया कर्ज लेकर भाग जाएगा तो धारावी के लोगों का क्या होगा। धारावी का विकास कैसे होगा। जब अडानी को चोर बोलो तो बीजेपी वाले पीछे पड़ जाते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है। भाकपा मुंबई सचिवमंडल सदस्य नसीरुल हक ने कहा कि भाकपा पिछली जनवरी से ही अडानी हटाओ, धारावी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। भाकपा ने बहुत सारी नुक्कड़ और मुहल्ला मीटिंग की, रैली निकाली, आज लड़ाई में सभी पार्टी साथ आई हैं। एक बहुत अच्छी बात है। यह प्रोजेक्ट फ्रॉड तरीके से फ्रॉड कारपोरेट अडानी को दे दिया गया है। जिसने अपने शेयरों का घोटाला कर पूरे हिन्दुस्तान के साथ धोखा किया है, पूरी दुनिया को धोखा दिया इसकी हिंडनबर्ग ने पोल खोल दी है। यह धारावी के लोगों के साथ भी धोखा कर जाएगा। बिड (निविदा) में है कि धारावी के लोगों को 10 किलो मीटर तक शिफ्ट किया जा सकता लेकिन धारावी के लोग बाहर नहीं जायेंगें यह संकल्प लेना है धारावीकर को और लड़ना है। धारावी के लोग धारावी की जमीन का विकास नहीं धारावी के लोगों का विकास चाहते हैं। धारावी में कामगार लोग रहते हैं जो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए छोटा छोटा कारोबार करते हैं। धारावी में लेदर उद्योग, बैग बनाने का धंधा, कपड़े पर जरी का धन्धा, फरसान, इडली डोसा का काम, गारमेंट इंडस्ट्री और पोटरी बनाने का काम करते हैं, धारावी के लोग इन सभी उद्योग का विकास चाहते हैं। शेकप नेता राजू कोरडे ने कहा अडानी को रियायत पर रियायत दी गयी है। दुबई की कम्पनी सेकलिंक को जिस धारावी प्रोजेक्ट की 2019 में बिड की कॉस्ट 27000 करोड़ रुपया थी उसे 7200 करोड़ में दिया गया था उसे कॉस्ट को कम कर 2023 में 19000 करोड़ रुपया कैसे किया गया इस तरह यह बिड 5069 करोड़ में फ्रॉड तरीके से अडानी को दिया गया है। साथ ही इस में 800 करोड़ रुपया की रेलवे की जमीन भी जोड़ दी गयी है। इस बिड में रोड नाला, मैदान, और 42 एकड़ का नेचर पार्क को भी जोड़ कर 10 एफएसआई दे कर फायदा पहुंचाया गया। शिव सेना धारावी विभाग प्रमुख विट्ठल पावर ने कहा कि धारावीकरो को अगर धारावी से बाहर फेका गया तो एक–एक धारावी के लोग रास्ते पर आ जाएंगे। आरपीआई के सिद्धार्थ कसारे ने कहा टाटा पावर के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन गया वहां के लोग का विकास कैसे होगा, कुम्हारवाडा में 1000 स्क्वेयर फीट से 2000 स्क्वेयर फीट का भट्टी है, उस भट्टी को कहां जगह मिलेगी, उसका विकास कैसे होगा। शिव सेना के महेश सावंत ने माहिम फाटक के गोदाम का मामला उठाया कि वहां 1000 से 1500 स्क्वेयर फीट का गोदाम है उसको कितनी जगह मिलेगी।

इस सभा में धारावीकरों की बड़ी भीड़ जुटी थी। भाकपा के प्रकाश नार्वेकर, चंद्रकांत शिंदे, आइयापिल्लै, शंकर कुंचिकोर्वे, लक्ष्मण कुंचिकोर्वे और चन्दन के नेतृत्व में एक रैली निकाली गयी जो एमपी नगर से अडानी हटाओ, धारावी बचाओ का नारा लगाते हुए सभा स्थल पर पहुंची थी। वहां पर रैली में आए भाकपा के कार्यकर्ताओं का जिसमें महिला बड़ी संख्या में थी, का नेतृत्व महिला फेडरेशन की नेता दीपाली कुंचिकोर्वे कर रही थी।

नसीरुल हक

विदित हो कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जो मिनी हिन्दुस्तान कहा जाता है, इसकी झोपड़ी, चाल और बिल्डिंग में हिन्दुस्तान के हर धर्म, जाति, सम्प्रदाय और अलग अलग भाषा बोली वाले लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। इस धारावी को उजाड़ने के लिए विकास के नाम पर अडानी को दे दिया गया है। धारावी में एक लाख से ज्यादा झोपड़ियां है परंतु पूर्व में किये गये सर्वे में मात्र 58 हजार झोपड़ियां को ही अधिकृत किया गया है, इतना ही अनधिकृत भी हैं। इन अनधिकृत झोपड़ियों का क्या होगा, क्या कारपोरेट सेक्टर की कम्पनी अडानी विकास के नाम पर उन्हें बेदखल कर देना चाहती है।

इससे पहले पूर्ववर्ती महाराष्ट्र सरकार 2019 में धारावी पुनर्विकास का जिम्मा दुबई की कम्पनी सेकलिंक को 7,200 करोड़ में दिया था जो रद्द कर दिया गया है, जिसमें धारावी का मात्र 178.3 हेक्टर जमीन ही थी, लेकिन वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ने धारावी की 178.3 हेक्टर जमीन और रेलवे की 47.3 हेक्टर को मात्र 5,069 करोड़ रुपये में दे दिया है। जबकि रेलवे की जमीन के लिए रेलवे को 800 करोड़ महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। यही 2,931 करोड़ रुपया का फायदा अडानी को पंहुचाया गया है।

अडानी की नजर धारावी की बेशकीमती जमीन पर है जो बिकेसी के नजदीक है, बिकेसी अब अंतर्राष्ट्रीय कामर्शियल सेंटर बन चुका है अब इसका विस्तार देकर बिकेसी–2 बनाने की योजना है। इसलिए धारावी की जमीन पर अडानी और अंतर्राष्ट्रीय कार्पोरेट की नजर है। इसका दूसरा कारण यह भी है की धारावी दादर, मटुन्गा, महिम, साईन सहित कई रेलवे स्टेशनों से घिरा हुआ है, पश्चिम और पूर्व दो एक्स्प्रेसवे के बीच बसा हुआ है, यहां से मेट्रो लाईन और बिकेसी में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने से इसका महत्व और बढ़ गया है। धारावी की जमीन की कीमत अब साउथ मुंबई के मालाबार हिल, निपेन्सी रोड या बांद्रा के पाली हिल्स से भी ज्यादा हो गयी है।

यहां धारावी में मेहनतकश जनता, कामगार लोग छोटे छोटे व्यवसायिक, कारोबारी मेहनत मशक्कत कर रोजी रोटी कमा रहे हैं, अदानी जिसे बेदखल कर यहाँ दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय कमर्शियल सेंटर, टावर, पांच सितारा होटलों, मॉल्स, कैसिनो, विदेशियों के हवाले कर देना चाहते हैं। इस धारावी की जमीन को अड़ानी अंतर्राष्टीय बाजार में कमर्शियल भाव से बेच देगा जिसे उसे 3 लाख करोड़ रुपया का फायदा होगा। इसलिए सरकार द्वारा विकास का प्रलोभन दिया जा रहा है। जबकि धारावी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता कर धारावीवासियों को अंधेरे में रखा गया है।

धारावी में एक लाख से ज्यादा आवास हैं और यहां हर घर के ऊपर मंजिला पर लघु और मध्यम उद्योग चलता है, जिस कारण धारावी एक औद्योगिक हब भी है। यहां लेदर प्रोडक्ट्स, कपड़े पर जरी वर्क, लेडीज गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट, नायलॉन बैग बनाने का काम, फरसान प्रोडक्टस, पार्टीज और भी अन्य सामग्रियां धारावी की झोपड़ियों में बनायी जाती हैं। जिसे ध्वस्त कर सरकार अडानी कारपोरेट और पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती है।

यहां लाखों मजदूर एसे हैं जो सस्ते भाड़े के घर में परिवार के साथ या संयुक्तरूप से रहते हैं, परंतु वह काम मुंबई के विकास के लिए मुंबई के अन्य जगहों पर कल कारखाने, कारपोरेट कम्पनियों, दफ्तरों में काम करते हैं। अब उनको सस्ता घर कहां मिलेगा यह भी एक सवाल बना हुआ है।

सवाल तो टाटा पावर का भी है, जिसके विकास का जवाब सरकार के पास भी नहीं। माहिम फाटक पर स्थित बड़े बड़े गोदाम का है उसका क्या होगा, सवाल कुम्हारवाड़ा का है जहाँ मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए बड़ी भिट्ठियां है, उसके उपर कारखाने और घर भी हैं उनका क्या होगा? लेबर कैंप मटुंगा का कुछ इलाका विकसित भी है तो कुछ बिल्डिंग में बड़ा बड़े फ्लैट्स हैं, तो कुछ चालों में बड़ा बड़ा घर है, उनका क्या होगा? उनको कितनी जगह मिलेगी? यह भी एक सवाल के घेरे में है।

धारावी के सभी राजनीतिक दलों का मानना है की हम लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं लेकिन विकास प्रत्येक धारावीकर का हो, यहां रहने वाले सभी को धारावी में ही बिल्डिंग बनाकर अपना बड़ा घर मिले, पात्र और अपात्र की बात खत्म कर नया सर्वे करा कर सभी को अपना घर मिले। यहां जो रोजी रोटी के लिए कारोबार या कल कारखाना या बिजनेस है उसका विकास हो उसको धारावी में ही जगह मिले, धारावी का औद्योगिक स्वरूप कायम रहे, यहां औद्योगिक हब बने। यहां भाड़े पर रहने वाले को भी सस्ते भाड़े का घर मिले। यहां स्कूल कालेज, खुला मैदान भी हो। एक भी धारावी वासियों को धारावी के बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए। अगर धारावी के पुनर्विकास के लिए बीजेपी शिवसेना (शिंदे गुट) सरकार का मन साफ होता तो सरकारी संस्थाएं म्हाडा, एमएमआरडीए और सिडको से पुनर्विकास और विकास कराना चाहिए था। जिस पर लोगों को भरोसा है। वह धारावी का पुनर्विकास एक फ्रॉड और क्रूर कारपोरेट को देना धारावी वासियों के साथ धोखा है।

धारावी के लोग इस बात को समझ रहे हैं अडानी कॉर्पोरेट धारावी का विकास करने नहीं आ रही है, बल्कि उनकी नजर धारावी की बेशकीमती जमीन पर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजार में बेच कर करोड़ों मुनाफा कमाना चाह रही है, उसके लिए धारावी ध्वस्त कर धारावीवासियों को धारावी से 10 किलोमीटर बाहर फेंक देने की योजना है। अडानी धारावीवासियों को जमीन बेदखल कर इस जमीन को अंतर्राष्ट्रीय बाजर बेच देगा जिसे यह अंतर्राष्ट्रीय सेंटर बन सके इसलिए हम लोग अडानी का विरोध कर रहे हैं।

जब नवंबर 2022 में धारावी को पुनर्विकास के लिए महाराष्ट्र की शिंदे–फडणवीस की सरकार में अडानी को दिया। उसी समय दिसम्बर 22 में ही सबसे पहले भाकपा मुंबई और धारावी ब्रांच ने संयुक्त मीटिंग कर धारावी के लोगों को उजड़ने से बचाने के लिए धारावीकर को न्याय दिलाने का संकल्प लिया और 'अडानी हटाओ, धारावी बचाओ' का नारा दिया और सभी कार्यकर्ता संघर्ष के लिए जमीन तैयार करने लग गए। जनवरी से मार्च 2023 में 2 दर्जन से ज्यादा नुक्कड़ और मुहल्ला मीटिंग और सभा की गयी और हैंडबिल का वितरण किया गया। अप्रैल 23 में 12 और 15 तारीख को धारावी में दो दिन का महामोर्चा निकाल कर अडानी हटाओ धारावी बचाओ को लेकर धारावी की आम जनता और कारोबारी को लड़ाई लड़ने के लिए जागृत किया। इस महामोर्चा में सुकुमार दामले, श्याम काले, प्रकाश रेड्डी, मिलिंद रनाडे, बबली रावत, चारुल जोशी, नसीरूल हक, चंद्रकांत शिंदे, और अन्य साथियों ने हिस्सा लिया था।

सभी दलों को एक साथ लाने में और अडानी हटाओ, धारावी बचाओ आंदोलन को मजबूत करने में प्रकाश रेड्डी, प्रकाश नार्वेकर, मिलिंद रनाडे, नसीरूल हक, चंद्रकांत शिंदे, शंकर, जमशेद आलम और धारावी भाकपा, कचरा वाहतुक श्रमिक संघ और स्थानान्तरित श्रमिक के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभायी, जो सराहनीय है।

परसाई को याद करते हुए

इस्पाती इरादों वाला कद्दावर लेखक

अभय नेमा

नई सरकार के अच्छे दिनों की बांट जोह रहा हूं। टमाटर हमारे ऊपर 35 रुपए पाव पड़ रहा है। स्विस बैंक से कालाधन लौटता नहीं दिखता। चहुं ओर धर्म की जय है। बुद्धिजीवियों को देश में नई ऊर्जा दिख रही है। देश के बारे में सोचता हूं तो परसाई बरबस ही याद आते हैं। परसाई ने अपने समय के राजनीतिक सवालों से सीधे मुठभेड़ करते हुए अपने लेखन से सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा। पत्रकारिता और साहित्य को समृद्ध करने इस लेखक ने नईदुनिया और देशबंधु समेत अन्य अखबारों में अपने साप्ताहिक स्तंभों से आजादी के बाद से 70 के दशक तक पाठकों को अपने कस्बे, शहर, प्रदेश, देश और अतंराराष्ट्रीय परिदृश्य से एक तार्किक चेतना के साथ अवगत कराया। मध्यम वर्ग की मनोवृत्तियों को रेखांकित किया। परसाई ने अपने कालम्स के जरिए जो लोक शिक्षण किया वह आज की हिंदी पत्रकारिता में दुर्लभ है। परसाई के लेखन की खासियत रोज–मर्रा की आसपास की घटनाओं की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक व्याप्ति थी। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद देश और दुनिया की सभी प्रमुख घटनाओं, आंदोलनों, और व्यक्तियों के बड़े सूक्ष्म और कलात्मक व्यंग्य चित्र उनके कालमों मिल जाएंगे।

1957 के बाद से नईदुनिया में छपने वाला –सुन भई साधो– नामक स्तंभ बड़ा लोकप्रिय था। परसाई इसमें कबीर के नाम से लिखते थे। वहीं जनयुग नईदिल्ली में 1965 से अदम के नाम से ये –माजरा क्या है– नामक स्तंभ अदम के नाम से लिखते थे। दैनिक देशबंधु में –पूछिये परसाई– से नामक स्तंभ बड़ा लोकप्रिय था, जिसमें परसाई पाठकों के सवालों के जवाब अपने विशिष्ट नजरिए से देते थे। इसी प्रकार अरस्तू की चिट्ठी के अंतर्गत लिखी गई चिट्ठियों में अपने समय के जीवन यथार्थ की सटीक तीखी आलोचना मिलती है। धार्मिक पाखंड, अमानवीय आचरण, सांप्रदायिकता के खिलाफ आजीवन अपनी कलम चलाई। स्वतंत्रता के बाद के सामाजिक यथार्थ को परसाई ने व्यंग्य की कलात्मक विधा से साधा और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद संभवतः सबसे बड़ी सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त किया। परसाई ने अथक लेखन किया। उनके समग्र लेखन में लघु कथात्मक व्यंग्य रचनाएं, दीर्घकथा, कहानियां, ललित विचारपरक तथ पत्रात्मक निबंध, राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय मसलों पर व्यंग्य निबंध, संपादकीय आलेख, साक्षात्कार, व्याख्यान और उपन्यास शामिल हैं। परसाई के व्यंग्य निबंध करीब 24 पुस्तकों में संकलित हैं। परसाई की प्रमुख पुस्तकों में सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निट्ल्ले की डायरी, पाखंड का आध्यात्म, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि प्रमुख हैं। परसाई की रचनाओं के फुटकर अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुए। मलयामल में उनकी सर्वाधिक 4 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। परसाई ने 1956 में वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन संपादन

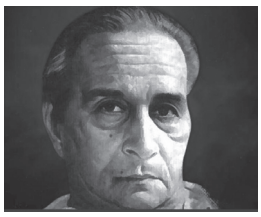

किया। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की मध्य प्रदेश में पुनः स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभायी थी।

उनका जन्म होशंगाबाद जिले के जामनी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। मेट्रिक के दौरान उनकी माताजी की मत्यु हो गई। पिता को असाध्य बीमारी के कारण गहन आर्थिक अभाव में उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। इस संघर्ष ने उन्हें इस्पाती इरादे दिए और समाज की बीमारियों को पकड़ने की दृष्टि दी। उन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। फिर खंडवा और जबलपुर में अध्यापन कार्य किया। 1943 से 1952 तक हाई स्कूल में अध्यापन किया और 1952 में इस्तीफा दे दिया। 1953 से 57 तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया और फिर नौकरी को अलविदा कह दिया। इसके बाद से आजीवन स्वतंत्र लेखन के बूते गुजर–बसर की। आजाद भारत की नब्ज पर परसाई का हाथ था और देश का तापमान उनकी रचनाओं से लोग जान लेते थे। सामाजिक, राजनीतिक जीवन की मूल्यहीनता का कोई भी पहलू उनकी विवेक दृष्टि से बच नहीं सका। समाज के उत्पीड़ित वर्ग, नारियों के प्रति परसाई में गहरी करुणा है। वे मनुष्य के ढोंग को निर्ममता से जाहिर करते हैं। उनकी रचनाओं से समकालीन भारतीय जीवन देखा–समझा जा सकता है।

परसाई का हमारे देश के एक आध्यात्मिक गुरु रजनीश के बारे में एक कोट है अपनी कोशिश से मैं अपने को श्रद्धेय बना सकता था। ताकत के लिए बिजली के इंजेक्शन देने वाले अपने को डाक्टर कहलवा देते हैं। मेरे शहर में एक अध्यापक ने नेम प्लेट पर नाम के आगे आचार्य लिखवा लिया था। मैं समझ गया कि यह आदमी ऊंचा जाएगा। वह गया। बंबई जाकर उसने नेमप्लेट में भगवान लिखवा दिया और आजकल मान्यता प्राप्त भगवान है। परसाई, वाल्तेयर, शा, रसेल, सार्त्र, कामू, गोर्की, मायकोवस्की जैसे सामाजिक सक्रियतावादी लेखकों की अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने लेखन को सामाजिक जिम्मेदारी का औजार और नागरिक कर्म की तरह अपनाया। अपने आसपास की दुनिया को परसाई की नजर से देखो तो रोमांच होता है, परसाई जिस तरह सामाजिक व्याधियों और विद्रूप को डायग्नोस करते है, वह पाठकों को शिक्षित करने के साथ दृष्टिसंपन्न करता है जो सामाजिक बदलाव का माध्यम बनते हैं। बुंदेली का हल्का सा शेड उनकी भाषा में गजब की चमक ला देता है। परसाई के गद्य में अद्भुत कलात्मकता है। भारतेंदु, प्रतापनारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, और प्रेमचंद के जीवंत गद्य का अगली कड़ी परसाई को कहा जा सकता है। परसाई का प्रभाव उनके समकालीन और बाद के कथाकारों शिवमूर्ति, अखिलेश, रवींद्रनाथ त्यागी, ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जनमेजय, स्वयंप्रकाश आदि को देखा जा सकता है।

परसाई अपनी रचनाओं में जिस तरह राजनीति से सीधी मुठभेड़ करते हैं उसका असर हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं के रचनाकारों पर दिखाई देता है। संक्षेप में परसाई का समूचा साहित्य समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और साहित्यिक परिदृश्य में एक रचनात्मक हस्तक्षेप है, जो हमें भारत में सामाजिक बदलाव के लिए संस्कारित करता है।

भाकपा ने देशभर में मनाया स्वतंत्रता दिवस

नई दिल्ली: भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भाकपा राज्य सचिव दिनेश वार्ष्णेय ने राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया गया। समारोह को प्रो. सुबोध मालाकार, शंकर लाल भाकपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं अमृता पाठक ने भी संबोधित किया। संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भाकपा की भूमिका की सराहना की। उन्होंने वर्तमान समय में समाज की समस्या पर भी प्रकाश डाला जिसका समाधान समाजवादी नीतियों के तहत किया जाना आवश्यक है। देश की राष्ट्रीय एकता की रक्षा करनी होगी।

अन्य प्रमुख व्यक्ति जो उपस्थित थे, उनमें केहर सिंह, रामराज, अबसार अहमद, उत्तर दिल्ली जिला सचिव संजीव कुमार राणा, एआईवायएफ सचिव शशि कुमार, बबन कुमार सिंह आदि शामिल थे।

पश्चिमी दिल्ली

14 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (पश्चिमी दिल्ली जिला परिषद्) कार्यालय प्रेम सागर गुप्ता भवन, कर्मपुरा में पार्टी की ओर से 76वाँ स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दिल्ली राज्य परिषद् के सचिव दिनेश चंद्र वार्ष्णेय ने कार्यालय पर भारतीय तिरंगा फहराया तथा उन्होंने कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुये भारत की स्वतंत्रता के लिये बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को याद किया।

ध्वजारोहन समारोह में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य तथा दिल्ली राज्य सचिव मंडल के सदस्य शंकर लाल, सचिवमंडल सदस्य अमृता पाठक, एआईवायएफ के महासचिव थिरुमलाई, दिल्ली राज्य परिषद् के सदस्य तथा एटक दिल्ली राज्य कमेटी के उपमहासचिव मुकेश कश्यप, दिल्ली राज्य परिषद् के सदस्य तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिमी दिल्ली जिला परिषद् के सहसचिव राजेश कश्यप, जिला सचिवमंडल के सदस्य बृजभूषण तिवारी, राममूर्ति, राजेंद्र प्रसाद, ब्रांच सचिव–सुनीता देवी, रेहाना खातून आदि उपस्थित थे।

आगरा (उप्र)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय कामरेड महादेव नारायण टंडन भवन पर 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न हुआ।

जिला मंत्री पूरन सिंह ने ध्वजारोहण किया। पूरन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझाते हुए मौजूदा दौर में मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने के प्रति साथियों से सावधान रहने की और लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करने की अपील की। शरीफ खान व मोहन सिंह जादूगर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में ताराचंद, एमपी दीक्षित, धर्मजीत, नीरज मिश्रा, पूरन चंद, हरी बाबू, योगेंद्र बघेल, महाराज सिंह भगोर, कृष्णा सेठी, कैलाश कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण शर्मा आदि लोग उपस्थित थे।

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

15 अगस्त 2023 आजादी की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बिलासपुर जिले के अपने विभिन्न शाखा कार्यालयों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा। सर्वप्रथम पुराना पावर हाउस जिला परिषद कार्यालय बिलासपुर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया उसके बाद। बूटा पारा शाखा कार्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सदस्य एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। कुटी पारा में भरत लाल दूरी की अगुवाई में झंडा फहराया गया तदुपरांत वार्ड नंबर 42 चंद्रशेखर आजाद नगर देवरीखुर्द में ध्वजारोहण एवं आजाद जी के मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया था। जिसमें ध्वजारोहण के बाद आमसभा का आयोजन किया गया था। आमसभा की अध्यक्षता काशीराम ठाकुर ने की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन शर्मा, युवा नेता विक्रांत शर्मा, संत निराला, धीरज शर्मा ने अपनी बात रखते हुए आमसभा को संबोधित किया और बताया कि किस कीमत पर 200 वर्ष की गुलामी से हमें आजादी मिली थी। इस बारे में आम लोगों को बताते हुए इस सभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई और रोजगार देने में विफल रहने एवं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर घेरते हुए केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा की गयी। साथ ही बताया गया कि सविधान की धारा 111और 255 को मनमाने ढंग से आम जानता के उपर थोपा जा रहा है। नूंह और मणिपुर में धार्मिक भावनाओं को भड़का कर संप्रदायिकता फैलायी जा रही है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आह्वान है कि 2024 में भाजपा हटाओ, देश और संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योदान देने वालों में पवन शर्मा जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एचडी पाइक, चिल्लू सिंह, काशीराम ठाकुर, विक्रांत शर्मा, संत निराला, पावेल शर्मा, लाल साहू, राजकुमार ढीमर, राम प्रसाद वैष्णव, बाबा खान, टिल्लू सिंह, प्रमोद मसीह, राजेश काशीराम ठाकुर, विनय शर्मा साधराम धुरी, धीरज शर्मा, गोकुल चौहान, सूरज लोधी, ईश्वर वस्त्र, पेशी लाल यादव, आकाश, चिल्लूसिंह, अंशू शुक्ला, वैभव पेसी यादव, अग्नि विजय सिंह, दल्लु यादव, जेठू राम मिश्रा, शोभू राम भोई, अशोक भोई, दिलीप धूरी, साधुराम धूरी, रवि भोई, मालिकराम बरगाह आदि शामिल थे।

परसाई का लेखन: डंडा मारने पर कम्बल से धूल झटक देने जैसा

विनीत तिवारी

कुछ दिन पहले एक कविता पर नजर पड़ी। आजकल कविताएँ भी दो श्रेणियों में बँट गई हैं – एक सोशल मीडिया वाली कविताएँ और दूसरी वाकई कविताएँ। बहरहाल यह कुछ सोशल मीडिया टाइप की कविता थी जिसका कहना यह था कि पाँच संगठनों द्वारा आयोजित संयुक्त गोष्टी में चंद लोग आकर बैठ जाते हैं, जिनमें से कुछ वक्ता हो जाते हैं और कुछ श्रोता। देश की समस्याओं पर सिर हिलाते हैं और एक–दूसरे की बात पर सहमति जताते हैं और इस तरह जन समस्याओं पर राष्ट्रीय चिंतन करके अगली गोष्ठी तक के लिए घर चले जाते हैं।

काफी लोगों को कवितानुमा व्यंग्य अच्छा भी लगा होगा किसी ने इसे विडम्बनायुक्त सच भी कहा। लेकिन ये था तो व्यंग्य ही। और इसमें शामिल था एक उपहास भी उनका जो समस्याओं के वास्तविक हल ढूँढ़ने के बजाय इस–उस तरह से अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मानकर खुश हो लेते हैं। लेकिन इसी में यह भी निहित है कि जो इंसान इस बात से उन लोगों के समूह पर व्यंग्य कस रहा है, जिनकी यह गोष्ठी उस इंसान की निगाह में फालतू है, हास्यास्पद है, वो जरूर ही कोई अन्य ऐसी उत्पादक गतिविधि कर रहा होगा जिसका महत्त्व ऐसी अनुत्पादक गोष्ठी से कहीं ज्यादा हो। कम से कम उसकी निगाह में तो हो। और हो सकता है कि ऐसी गोष्ठी पर व्यंग्य करनेवाला व्यंग्यकार दलाली या भ्रष्टाचार से भी पैसे कमाना बेहतर मानता हो क्योंकि उसमें वो कुछ धन अर्जित कर रहा है। क्या हमारी नजरों में वो व्यंग्य करने का हक रखता है? कुछ लोग दुनिया की चिंता कर रहे हैं आपस में मिलकर। गोष्ठी कर रहे हैं। जाहिर है उनकी चिंता से कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यंग्य कर रहा है, मान लीजिए वो सुबह–शाम पैसे कमाने की जुगत में लगा है, या नहीं भी लगा है तो उसका नजरिया ये है कि 'कोई नृप होये हमें का हानि' या 'मस्तराम मस्ती में और आग लगे बस्ती में' तो क्या उसका इन गोष्ठी करने वालों पर व्यंग्य करना जायज कहा जा सकेगा? मेरे ख्याल से हरगिज नहीं।

व्यंग्य इसीलिए काफी कठिन चीज है, दोधारी तलवार है। अगर आप किसी पर नाराज होते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, तो भी अपनी गलती समझ आने पर अपने व्यवहार पर माफी माँगना आसान होता है। लेकिन यदि आप किसी पर गलत व्यंग्य करते हैं, और अगर आप ऐसा करके कभी अपनी गलती का एहसास करते हैं तो वैसी स्थिति में माफी मांगना भी कठिन हो जाता है। हरिशंकर परसाई इसीलिए कहते थे कि व्यंग्य वहीं कारगर होगा जहाँ लोगों को शर्म आती होगी। बेशर्मो के समाज में व्यंग्य पर लोग हो–हो करके हँस देंगे और जो कर रहे थे, वो करते रहेंगे।

हरिशंकर परसाई को आमतौर पर हिंदीभाषी लोग एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में जानते हैं लेकिन वे सिर्फ व्यंग्यकार ही नहीं एक बड़े लेखक और दार्शनिक भी थे। अपने आसपास के समाज और देश–दुनिया में घट रहीं सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर उनकी पैनी नजर हुआ करती थी और वे सहज सामान्य भाषा में व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी टिप्पणी इन घटनाओं पर और उनमें शामिल विरोधाभासों पर किया करते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि जैसे आजादी के पहले के भारतीय समाज को जानने के लिए प्रेमचंद को पढ़ना जरूरी है, वैसे ही आजादी के बाद हिंदी समाज को और उसकी चेतना के बदलते स्तर को जानने के लिए परसाई को पढ़ना नितांत आवश्यक है।

उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्यप्रदेश के जमानी के होशंगाबाद में हुआ था। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश भाग जबलपुर में ही काटा। जबलपुर में ही वे अपने जमाने के हिंदी के यशस्वी कवि मुक्तिबोध के संपर्क में भी आये और साथ ही जबलपुर में आर्डिनेंस और व्हीकल्स फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों के संघर्षों में भी भागीदार हुए। उस वक्त 'देशबंधु' और 'नईदुनिया' समूचे हिंदी क्षेत्र के बड़े अखबार माने जाते थे और इनकी पठनीयता भी काफी थी। इन अखबारों में परसाई जी के अनेक वर्षों तक कभी दैनिक तो कभी साप्ताहिक स्तम्भ छपते रहे। इन स्तम्भों में दुनिया के तमाम विषयों पर उनका लेखन साधारण–सहज भाषा में होता था। यह लेखन एक तरह से युवाओं और बुजुर्गों, महिलाओं और पुरुषों को एक नयी प्रगतिशील दृष्टि देता था और बनी–बनाई रूढ़िगत सोच पर प्रहार करता था, चाहे वह धर्म हो, सामाजिक रीति–रिवाज हों या जाति व्यवस्था हो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति से लेकर देश और मोहल्ले की राजनीति और सामान्य मनुष्यों के व्यवहार और उसके छद्म को उनका लेखन तार–तार कर देता है। हालाँकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मामलों पर ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन कभी–कभी अमेरिकी साम्राज्यवाद की साजिश को उन्होंने आम लोगों के सामने अपनी साधारण सी विलक्षण भाषा में उजागर किया। उनकी अधिकांश रचनाओं के में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, रीति–रिवाजों में शामिल दोहरे मापदंड, पितृसत्ता, जातिवाद और साम्प्रदायिकता पर हमला बिंदु रहा।

उन्होंने खुद लिखा है कि लोगों की चमड़ी मोटी होती जा रही है। पहले जो लोग रिश्वत लेते वक्त थोड़ी आड़ रखा करते थे, अब वे खुलेआम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। और इसकी उन्हें कोई शर्म नहीं होती। परसाई लिखते हैं कि मैं जिन लोगों को पात्र बनाकर उनके भ्रष्टाचार या उनके दोहरे आचरण की पोल खोलता हूँ, कुछ दिन बाद वे ही मुझे अपने समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाते हैं।

इस व्यंग्य के माध्यम से परसाई ने अपने जीते–जी ही वो सूत्र दे दिया था कि कौन होंगे जो उनकी याद इसलिए करेंगे कि वो बड़े लेखक थे, और कौन होंगे जो उनके लेखन को याद करेंगे जो उन्होंने लिखा और उसे पढ़कर पहले से बेहतर मनुष्य बनेंगे। आजकल सुनने में आता है कि परसाई जी के व्यंग्य की, उनकी सरल–सहज भाषा की,

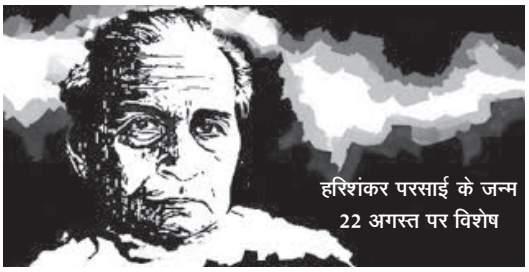

उनको मिले पुरस्कारों और उनके प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ाव की चर्चाएँ चलती रहती हैं। कभी–कभी उनके शराब पीने की भी चर्चा होती है। लेकिन उनके राजनीतिक धारदार विचारों की चर्चा कम होती है। परसाई या हबीब तनवीर हों या अपने समय के बड़े कलाकार–साहित्यकार आदि, उन्हें प्रासंगिक बनाये रखते हुए उन्हें अप्रासंगिक करने की साजिश यही होती है कि हम उनकी भाषा, और अन्य चीजों की बातों में उलझे रहें और उसके राजनीतिक विचारों को अन्यान्य बातों के ढेर में छिपा दें।

हमें परसाई को ऐसे प्रासंगिक होने से बचाना है जिसमें से उनके विचार निकाल दिए जाएँ।

प्रेमचंद अपने आपको कलम का मजदूर कहते थे। वे जब तक लिख नहीं लेते थे रोज तब तक उनके पेट का इंतजाम नहीं होता था। परसाई ने भी प्रतिबद्ध लेखन को ही अपने जीवन यापन का जरिया बनाया। लेकिन प्रेमचंद और परसाई, दोनों ने ही लेखन से पैसे कमाने के फेर में अपनी वैचारिक ईमानदारी को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनके निशाने पर भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और गाँधी–नेहरू तक की नीतियाँ भी रहीं। कांग्रेस हो या उस वक्त का जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, चाहे गाँधी हों या नेहरू, इंदिरा गाँधी हों या मोरारजी देसाई या जयप्रकाश, किसी भी धर्म के धर्मग्रन्थ हों या धर्मगुरू, परसाई ने किसी को भी नहीं बख्शा। विचारधारा के स्तर पर उन्होंने अपना बौद्धिक स्रोत मार्क्सवाद और वैज्ञानिक समाजवाद को बनाया। इन औजारों की वजह से वे अपने वर्तमान, अतीत और आगामी समय का विश्लेषण कर सके। आज बहुत सारे लोग परसाई के लेखन को तो स्वीकार करते हैं लेकिन परसाई की तरह उनके वैचारिक और जीवन मूल्यों को अलग रखकर देखते हैं। जबकि यदि परसाई के लेखन से राजनीतिक और वैचारिक समझ निकाल दी जाये तो परसाई के लेखन को बेजान कर देने जैसा होगा। या कहिये कि किसी दार्शनिक निबंध को चुटकुले में बदलने जैसा होगा।

परसाई के लेखन की एक खासियत तो यही है कि वह ज्ञान और विज्ञान की, या सही और गलत की बात करने के लिए साधारण बातचीत की भाषा चुनते हैं। वे कहीं से मोटे – मोटे उद्धरण या भारी–भरकम शब्दों का पहाड़ नहीं खड़ा करते और लोगों की चेतना पर जमी हुई जंग की मोटी परत को अपनी साधारण भाषा के व्यंग्य के डंडे से झाड़ देते हैं। परसाई के व्यंग्य पढ़कर पाठक तिलमिलाता भी है लेकिन उनके तर्क के आगे निरुत्तर होकर आखिर वह मान भी जाता है। तो एक तरह से परसाई के व्यंग्य की कड़वी गोली खाकर ऐसे पाठकों का बुखार ठीक हो जाता है जिनके दिमागों पर आडम्बर और अंध श्रद्धा का पर्दा पड़ा रहता है।

कुछ बार ऐसा भी हुआ है जब परसाई के ऐसे लेखन से लोगों का विवेक जागृत होता देख कुछ संगठनों को लगा कि ऐसे तो हमारी दूकान ही बंद हो जाएगी जो जाति और धर्म के आधार पर संगठन चला रहे थे। उनमें से कुछ ने एकाध बार परसाई जी पर हमला भी किया लेकिन परसाई जिस प्रगतिशील परंपरा के लेखक थे, वहाँ लेखन भय से जीतकर ही किया जाता है। आज जब वरवर राव, सुधा भरद्वाज, आनंद तेलतुम्डे, गौतम नवलखा, शोमा सेन, हैनी बाबू, जी. एन. साईबाबा आदि लेखक–बुद्धिजीवी झूठे मामलों में फँसाकर जेल में बंद किये गए थे और अनेक आज भी बंद हैं, वहाँ ऐसे दौर को देखकर लगता है कि परसाई का लेखन यकीनन उन्हें भी अब तक जेल पहुँचा चुका होता या उनकी जान पर ही बन आती।

परसाई अपने लेखन को क्षण का लेखन मानते थे। उनका मानना था कि जो अपने समय के प्रति सचेत नहीं है, उस पर खामोश है तो ऐसे शाश्वत लेखन से मुझे कोई लेना–देना नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने आसपास मौजूद हर सामाजिक–राजनीतिक मसले पर टिप्पणियां कीं। प्रेम पर और प्रेम के प्रदर्शन और उसकी निस्सारता पर उनके कुछ व्यंग्य लेख तो अद्भुत हैं। अपने समकालीनों पर उनके लिखे संस्मरण भी बहुत दिलचस्प हैं।

अनेक लोग उन्हें व्यंग्यकार मानते हैं जबकि वे खुद को ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था और जो सही भी है कि व्यंग्य एक भाव है जो कविता में भी हो सकता है, कहानी में और निबंध या पत्रों में भी। वो अलग से कोई विधा नहीं है। कुछ लोग व्यंग्य को हास्य–व्यंग्य समझते हैं। परसाई इसे भी सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अगर कोई सड़क पर फिसल कर गिर जाये तो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। यह हास्य है। लेकिन अगर किसी को गिरने वाले पर हंसते लोगों को देखकर गिरे हुए को उठाने का ख्याल आये तो ये व्यंग्य है। वे कहते थे कि व्यंग्य करुणा से पैदा होता है इसलिए व्यंग्य को जिम्मेदार होना चाहिए।

उनके लेखन का दायरा बहुत बड़ा रहा। उनका रचा गया विपुल लेखन परसाई रचनावली में इकट्ठा किया गया है। परसाई ने हिंदी साहित्य के लेखकों की कम से कम तीन–चार पीढ़ियों पर अपना असर छोड़ा है चाहे वह कोई भी विधा हो। परसाई की याद करते हुए राग–दरबारी के श्रीलाल शुक्ल और शरद जोशी की याद बेशक की जानी चाहिए लेकिन इन सभी की अपनी–अपनी विशिष्टता थी। परसाई का लेखन बहुत बड़ी रेंज में था और उनके पाठकों का दायरा भी बहुत बड़ा था। प्रगतिशील लेखन के उस्ताद लोग आज भी नए आने वालों को परसाई पढ़ने की सलाह देते हैं। यह एक तरह से लेखन की दुनिया में शामिल होने से पहले बाहर की धूल–मिटटी झाड़ने–पोंछने जैसा है। परसाई को थोड़े–थोड़े अंतराल पर उन्हें भी पढ़ना चाहिए जो पक चुके हैं ताकि परसाई का लेखन उन्हें उनके कोने में छिपे आत्म से साक्षात्कार करवा दे और बताये कि नारे और मुहावरे तो तुमने रट लिए, और जीवन में काम उलटे कर रहे हो? प्रगतिशील और आधुनिक बनते हो और दहेज ले रहे हो? जाति में और धार्मिक आडम्बरों में यकीन कर रहे हो?

यहाँ तक कि परसाई देश और राष्ट्र की भक्ति के नाम पर खड़े गए तूमार को भी अपने लेखन में पूरी तार्किकता के साथ ढहा देते हैं।

परसाई का लेखन समय के साथ जीवन में आ जाने वाले ऐसे विकारों को ऐसे ही निकाल देता है जैसे डंडे से मारने पर कम्बल से धूल झटक जाती है।

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस भाषण...

पेज 3 से जारी...

है। सांस्कृतिक विविधता और मेलजोल की संस्कृति खतरे में है।

भारत में लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है। वी.डेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत अनेक देशों जैसे कि तंजानिया, बोलिविया, सिंगापुर, मैक्सिको और नाइजीरिया से भी नीचे108वें स्थान पर है; उसमें चुनावी तानाशाही (इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इकोनोमिस्ट इन्टेलीजेंस यूनिट के भूमंडलीय लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को 44वें स्थान पर रखा गया है और एक दोषपूर्ण लोकतंत्र (फ्लॉड डेमोक्रेसी) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता और अस्तित्व के लिए एक आवश्यक तत्व है परंतु मोदी के कार्यकाल में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। प्रेस की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और वस्तुपरकता का क्षरण हो गया है।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स द्वारा संकलित एवं प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत अत्यंत नीचे 180वें स्थान पर है। 2014 में भारत 140वें स्थान पर था। जाहिर है मोदी के कार्यकाल में भारत 21 स्थान नीचे गिर चुका है।

पिछले वर्षों में राजनीति में धन–बल और बाहुबल हावी हो गया है। राजनीति केवल पैसे वालों का खेल बन गया है। लोकतंत्र केवल मताधिकार तक सीमित हो गया है। राजनीति में नफरत बढ़ी है। राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी के अनुसार, लोकसभा के 43 वर्तमान संसद सदस्यों की अपराधिक पृष्ठभूमि रही है और अपराधिक पृष्ठभूमि वालों के चुनाव जीतने की अधिक संभावना रहती है। इनमें बड़ी संख्या में संसद सदस्य भाजपा के हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी युवा शक्ति में पूरी आस्था है। क्या खाक आस्था है जब उन्हें सड़कों पर भटकते हुए करोड़ों युवाओं को रोजगार की चिंता ही नहीं है? नया रोजगार पैदा करना तो दूर रहा यह सरकार पुराने रोजगार को खत्म कर रही है; यहां तक कि बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में पदों को खाली रख रही है। 1 मार्च 2021 की स्थिति कि अनुसार, केंद्र सरकार में ही लगभग 9.79 लाख पद खाली पड़े थे। रेलवे में करीब ढाई लाख पद खाली पड़े हैं। पिछले दस वर्षों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लगभग 2.7 लाख रोजगार कम हो गए।

यह सरकार अमीरों के पक्ष में काम करती है जिसके चलते अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब हो रहे हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 (जिसे थोमस पिकेटी और उनके सहयोगियों ने तैयार किया) से पता चलता है कि गरीबों और अमीरों के बीच फासला इतना बढ़ गया है जितना आज से पहले कभी नहीं रहा; शीर्ष के 10 प्रतिशत के पास 57 प्रतिशत राष्ट्रीय आमदनी चली जाती है जबकि आबादी के निचले 50 प्रतिशत लोगों के हिस्से में आमदनी का केवल 13 प्रतिशत हिस्सा आता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत के 84 प्रतिशत परिवारों की आमदनी कम हुई जबकि खरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गरीबी, भूख, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती असमानता जैसी किसी समस्या का जिक्र ही नहीं किया जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या हैं।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दर:

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रूपये

खाता नाम: **मुक्ति संघर्ष वीकली**
बैंक: **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्या: **1033004704**
आईएफसी कोड: **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखें:
व्यवस्थापक: मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोट: डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक'' के नाम होना चाहिए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

तोड़ी जा रही है स्वतंत्रता आंदोलन की ...

पेज 1 से जारी...

आरएसएस–भाजपा का घृणित बुलडोजर क्षेत्र में स्थायी शांति और सद्भाव की संभावना को भी ध्वस्त कर रहा है। फिर भी, सहानुभूति और चिंता की कमी स्पष्ट है। गांधी जी ने अपने कमजोर शरीर के साथ एक साधारण धोती लपेटकर क्षेत्र का दौरा किया क्योंकि वे अपने ही लोगों से नहीं डरते थे। जो लोग बख्तरबंद काफिलों में चल रहे हैं, उनकी लोगों में उस विश्वास में कमी है।

हमें अपने देश और अपने नेतृत्व के लिए वास्तव में कठिन समय में अंग्रेजों से आजादी मिली। आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा पलायन तब सामने आया जब यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा फहराया गया। वे नेता, चाहे गांधी, नेहरू, पटेल या अंबेडकर या कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की भरी पूरी आकाशगंगा थी, परंतु वे सभी लोगों के लिए वास्तविक चिंता के साथ संकट के उस मौके पर खड़े हुए, चुनौतियों का बहादुरी से सामना किया और उस देश को आकार दिया जिसे हम सभी प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं।

पूरी दुनिया को हमारे जैसे गरीब देश में लोकतंत्र के अस्तित्व पर संदेह था, जिसने हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा का तांडव देखा था। फिर भी, हमारे नेताओं ने भारत की धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी नींव रखने के लिए अथक प्रयास किया, जिस पर 26 जनवरी, 1950 को हमारे गणतंत्र का उदय हुआ।

भारत में लोकतंत्र के अस्तित्व पर संदेह करने वाले सभी विदेशी नहीं थे। घर के भीतर गोलवलकर और सावरकर के अनुयायियों को प्रतिनिधि लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने और हिंदू–मुस्लिम एकता की रक्षा करने के लिए महात्मा गांधी को दण्ड़ दिया, दण्ड़ जो उनकी जान लेने से कम नहीं था। हमारे देश ने उस आपदा का भी बहादुरी से सामना किया और भारत के लोगों ने कठिन समय में अपनी एकता और कड़ी मेहनत से देश का नाम हर क्षेत्र में रोशन किया। 2014 में नरेंद्र मोदी को जो मिला वह एक स्थिर लोकतंत्र था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की आधारशिला पर बना और हमारे संविधान की दृष्टि से निर्देशित था। उनके शासनकाल में पिछले 9 साल ज्यादातर उस दृष्टिकोण को कुचलने और भारत के लोगों की आकांक्षाओं को कुचलने के रहे हैं। जिस सहानुभूति और साहस की हमने पहले बात की थी वह कहीं नजर नहीं आ रहा है और भारत को आरएसएस–भाजपा के सत्ता में बने रहने के लिए विभाजित किया जा रहा है। यही वह चुनौती है जिसका आज हमारी बहुमूल्य स्वतंत्रता सामना कर रही है और लोगों को इसका एहसास हो गया है। वे अब वर्तमान शासकों द्वारा भारत के विचार पर किए जा रहे हमले को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे वैसे ही एकजुट हो रहे हैं जैसे उन्होंने ब्रिटिश राज को हराने के लिए किया था। एकजुट होकर, वे ब्रिटिश पिट्ठुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। गांधी, नेहरू, पटेल और अंबेडकर का समावेशी भारत सहानुभूति और साहस के साथ उभरेगा और गोलवलकर और सावरकर की घृणित विचारधारा से अधिक मजबूत साबित होगा।

मोदी गद्दी छोडो के नारे के साथ देशभर...

पेज 10 से जारी...

मनरेगा मजदूर संघ एटक, एनएमडीसी, एस के एम एस, स्टील प्लांट, एल्यूमीनियम एम्प्लाइज यूनियन, एससीएल, कोयला खदान, आदि के साथियों की भागीदारी महापड़ाव के इस आयोजन में रहीं।

छत्तीसगढ़ राज्य एटक के महासचिव हरिनाथ सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी देश की बड़े ट्रेड यूनियनों से हैं हम छत्तीसगढ़ में उनका नेतृत्व करते हैं जिस प्रकार आज हम सभी एक साथ मिलकर इस महापड़ाव का आयोजन व काम कर रहे हैं, हम सब को एकसाथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मुझसे पहले के वक्ताओं ने अपने अपने अभिभाषण में देश के हालातों व मजदूरों की स्थिति पर जो बात रखी है वह सब सच है और सभी को ज्ञात है। परन्तु मैं जन संगठनों के प्रमुख साथियों से कहना चाहता हूँ, कि मजदूरों की लड़ाई, हक अधिकार, समस्या, एवं मजदूरों को संगठित करने के लिए आरामदायक आफिस से निकल कर काम करने की जरूरत है। आरामदायक आफिस में रह कर उन्हें संगठित नहीं किया जा सकता है। उनसे मिलकर, उनके बीच रहकर, जाकर जमीन स्तर पर काम करने की जरूरत है। खास तौर पर असंगठित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि देश में 75 प्रतिशत आबादी असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के इस महापड़ाव में राज्य एटक अध्यक्ष आर डी सी पी राव, सहायक सचिव राजेश संधू, सी आर बक्शी, दीपेश मिश्रा एवं महिला साथी संतोषी बरेठ ने भी अपने अपने विचार रखें एवं मंच का संचालन लिंगराज नायक के द्वारा किया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर रायपुर (छ. ग.) में आयोजित महापड़ाव में इंटक, एटक, सीटू, एक्टू, बी एस एन एल, एल आई सी, एच एम एस, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, बैंक आदि ट्रेड यूनियनों ने अपनी भागीदारी निभाई।

केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों...

पेज 16 से जारी...

2) संयुक्त बैठकें, रैलियां, जुलूस, धरने, सेमिनार आदि निम्न तिथियों को आयोजित किए जाएंगे:

(क) 21 अगस्त 2023; (ख) 21 सितंबर 2023; (ग) 21 अक्टूबर 2023 ।

(3) 21 और 22 नवंबर को ''रद्द करो/बगैर गारंटी एनपीएस को वापिस लो और परिभाषित एवं गांरटीशुदा पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की एकल मांग के लिए ''अनिश्चितकालीन हड़ताल'' के समर्थन में सभी संघटक संगठन हड़ताल मतदान (गुप्त मतदान) लेंगे।

4. पेंशन अधिकार विशाल रैली के निर्णय अनुसार जेएफआरओपीएस/एनजेसीए की संचालन समिति हड़ताल नोटिस के दिन की और ''अनिश्चितकालीन हड़ताल'' शुरू करने वाले दिन की घोषणा करेगी।

(5) जेएफआरओपीएस/एनजीसीए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और समर्थन संगठनों के परामर्श से हड़ताल के दौरान ''भारत बंद'' का आह्वान भी करेंगे।

रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए 1.5 लाख कर्मचारियों का दृढ़ संकल्प हैं कि यदि नए पेंशन सिस्टम को रद्द नहीं किया गया तो तीन करोड़ सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य जो कि लगभग 10 करोड़ होंगे वे इस सरकार को वोट नहीं देंगे, इसे सबक सिखाने के लिए। सरकारी कर्मचरियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अब मंच तैयार कर लिया है।

बेन ब्रैडली: मेरठ षडयंत्र केस के अभियुक्त

पेज 5 से जारी...

''यह भी संभव है कि राष्ट्रीय कांग्रेस अपने संगठन और कार्यक्रम में और अधिक परिवर्तन करके... मोर्चे को साकार करने का रूप ले ले।''

इसने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का नारा भी दोहराया। यह मांग सीपीआई ने बहुत पहले 1928 में ही उठाई थी।

ये थीसिस सीपीआई की साम्राज्यवाद–विरोधी लाइन के लिए एक मजबूत आधार बन गए।

7वीं कॉमिन्टर्न कांग्रेस के बाद ब्रैडली को ईसीसीआई (कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारी समिति) में भारत का प्रभारी बनाया गया।

साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीग

रेजिनाल्ड ब्रिजमैन के साथ, ब्रैडली ने लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म (एलएआई) या 'साम्राज्यवाद विरोधी लीग' के ब्रिटिश अनुभाग का आयोजन किया, अंततः इसके सचिव बने। 1937 में लीग को भंग कर दिया गया।

ब्रैडली एक इंजीनियर के रूप में अपने काम पर लौट आये। लीग की स्थापना 1927 में हुई थी, और इसने एक महान भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख नेता, सचिवों में से एक थे।

सीपीजीबी नेता

इस बीच, आरपीडी, हैरी पोलिट, स्प्रिंगहॉल, बिल रस्ट और अन्य के साथ काम करते हुए ब्रैडली एक महत्वपूर्ण सीपीजीबी नेता बन गए। 1940 में लंदन में एम्पायर डे कार्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उन्हों ने सीपीजीबी के औपनिवेशिक सूचना ब्यूरो के अंग के रूप में 'इनसाइड द एम्पायर' नामक एक नियमित समाचार पत्र की स्थापना की।

ब्यूरो साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीग से विकसित हुआ था। उन्हें सीपीजीबी की औपनिवेशिक समिति का प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने सीपीजीबी अखबार 'डेली वर्कर' में सर्कुलेशन मैनेजर के रूप में काम किया और इसके सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया।

ब्रैडली 1930–40 के दशक में इंडिया लीग की बैठकों में नियमित भागीदार और वक्ता थे। इन बैठकों के दौरान, वह मुल्क राज आनंद, इकबाल सिंह, कृष्णराव शेल्वंकर, सशधर सिन्हा, कृष्ण मेनन आदि जैसे प्रमुख भारतीयों के संपर्क में आए। इंडिया लीग ने ब्रैडली और साथी कम्युनिस्टों को अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया। लीग के साथ सीपीजीबी के सहयोग ने ब्रिटिश श्रमिक वर्ग को भारत की दुर्दशा के बारे में जागरूक करने का काम किया। ब्रैडली ने माइकल कैरिट और हैरी पोलिट के साथ मिलकर मार्क्सवाद का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन में अग्रणी भारतीय कम्युनिस्टों की मदद की।

ब्रैडली ने जुलाई 1939 में भारतीय फेरीवालों और नाविकों के एक सम्मेलन की योजना बनाई और ब्रिटेन में श्रमिक वर्ग के भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1942 में 'इंडियाः व्हाट वी इन ब्रिटेन मस्ट डू' पुस्तक और कई अन्य पुस्तकें प्रकाशित कीं।

1 जनवरी, 1957 को बेन ब्रैडली की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में चीन और भारत की सरकारों के आधिकारिक प्रतिनिधि शामिल हुए। उनके दस्तावेज हमारे श्रमिक वर्ग और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ–साथ सीपीआई और सीपीजीबी के इतिहास का एक अमूल्य स्रोत हैं।

कुछ सामयिक मुद्दे और घटनाक्रम

पेज 8 से जारी...

किसी भी धर्म में विश्वास करने का अधिकार या किसी भी धर्म के अनुसार जीने का अधिकार मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा सुनिश्चित धार्मिक स्वतंत्रता में धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने और पालन करने का अधिकार भी शामिल हैं, इसलिए आध्यात्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का कोई भी कदम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

प्रस्ताव में कहा गया है कि धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है लेकिन इस तरह का कानून (समान संहिता कानून) यदि लागू किया जाता है तो यह मौलिक अधिकारों से इनकार करने के बराबर होगा। इससे पहले, केरल विधान सभा ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था और वह उस तरह का प्रस्ताव पारित करने वाली भारत की पहली विधान सभा थी।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 20 – 26 अगस्त, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 18.8.2023

गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए

केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों का अनिश्चित हड़ताल का आह्वान

सी. श्रीकुमार

नई दिल्ली,14 अगस्त 23023: राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों के प्रदर्शन, 2003 के दौरान वाजपेयी नीत भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी रहित राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (नो गारंटी नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के विरोध में लगातार बढ़ रहे हैं। यह पेंशन व्यवस्था 01 जनवरी 2004 को या इसके बाद नियुक्त केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी। शासकीय कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों की फेडरेशनों और यूनियनों ने इस पेंशन सिस्टम को रद्द करने की मांग उठाई है और मांग की है कि पुरानी परिभाषित गारंटीशुदा पेंशन स्कीम फिर से बहाल की जाए। नेशनल पेंशन सिस्टम के विरोध में देश भर में प्रदर्शन और धरनों की गति बढ़ रही है क्योंकि एन.पी.एस. के अंतर्गत शासित कर्मचारियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में एनपीएस के तहत राज्य कर्मचारियों की संख्या लगभग 60 लाख से ज्यादा है और इस एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 20 लाख है।

2003 में भाजपा सरकार ने इस एनपीएस की जोर–शोर से घोषणा की और तर्क दिया कि एनपीएस बेहतर है पुरानी पेंशन स्कीम से चूंकि एनपीएस के तहत लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। वास्तव में जब कर्मचारी संगठनों ने इस एनपीएस के विरोध में प्रदर्शन किया, तब भारत सरकार ने 2007 में लिखित आश्वासन दिया कि एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम से ज्यादा होगी। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को इस एनपीएस से जो वास्तविक लाभ/ पेंशन मिल रही है उससे कर्मचारियों को एनपीएस के वादों से विश्वास टूट गया है।

पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार, 10 साल की सेवा के बाद कर्मचारी पात्र है पेंशन के रूप में बेसिक पे स्केल के 50 प्रतिशत का जो कि न्यूनतम 9000 रुपये+महंगाई भत्ता पाने का। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी पेंशन के 40 प्रतिशत को कम्यूट कर सकता है और सेवानिवृत्ति के समय अग्रिम राशि के बतौर ले सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुरानी पेंशन पर महंगाई राहत की दो किस्तें भी मिलती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में यह भी प्रावधान है कि पेंशन के कम्यूट किए गए भाग की फिर से 15 साल के बाद बहाली हो जाएगी। 80 साल की उम्र के बाद प्रतिशत के आधार पर पेंशन राशि बढ़ जाती है। कर्मचारी को ये लाभ पेंशन में बिना किसी योगदान के मिल जाते थे। फिर भी इनमें से कोई भी लाभ इस नई पेंशन सिस्टम में नहीं हैं।

इस नई पेंशन सिस्टम में कर्मचारी का योगदान अपने वेतन (मूल वेतन+डी.ए.) का सरकार का उस वेतन के 14 प्रतिशत का योगदान होता है। इस पेंशन योगदान को सरकार विभिन्न चीजों में निवेश करती है और इन निवेशों/ वार्षिकवृत्ति से पेंशन का भुगतान किया जाता है। संक्षेप में सरकारी कर्मचरियों की पेंशन बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भर करती है ।एनपीएस के बीस सालों के बाद हम देख रहे हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एनपीएस से नाममात्र की राशि बतौर पेंशन प्रतिमाह 2,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये मिल रही है और यह राशि पेंशनभोगी की मृत्यु तक स्थिर रहती है। ये तथ्य एनपीएस के बारे में सरकार के वादों के झूठों का खुलासा करते हैं इसलिए सरकारी कर्मचारियों के बीच क्रोध, निराशा और असंतोष है।

कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसने भाजपा और अन्य दलों के समर्थन से पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) 2011 में पास किया था। इस विधयेक का वाम दलों ने विरोध किया था अब कांग्रेस की जिन राज्यों में सत्ता है जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश वहां उसने एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी शुरू की है।

झारखंड और पंजाब सरकार ने भी एनपीएस को रद्द कर दिया है। जब से कांग्रेस सरकार ने यह घोषणा की है कि यदि वह सत्ता में आएगी तो वह पुरानी स्कीम फिर से बहाल करेगी, यह केरल सरकार समेत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना , उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों पर पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने के लिए दबाव देगा। फिर भी भारत सरकार और पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण कर्मचरिणयों के पेंशन कोष को उन राज्य सरकारों को देने से मना कर रही है जिन राज्यों ने पेंशन सिस्टम को रद्द कर दिया है। इनका कहना है कि यह धन कर्मचारियों का है और इसको वापिस नहीं लौटाया जा सकता। सभी राज्यों में नई पेंशन स्कीम के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन जिसमें अध्यापकों के संगठन भी हैं उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मंच को संघटित किया है इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठनों के अलावा रेल, डाक, रक्षा, आयकर, अकाउंट और ऑडिट कर्मचारियों के फेडरेशनों और यूनियनें भी शामिल हैं। देश भर में प्रदर्शनों और आगामी चुनावों के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एनपीएस में सुधार की सिफारिशों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ने कमेटी को निर्देशित शर्तों को अस्वीकार करते हुए मांग की है कि इसका केवल एकमात्र समाधान एनपीएस को निरस्त करना और परिभाषित एवं गारंटीशुदा पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करना है।

पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ने 10 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक विशाल रैली नई दिल्ली के रामलीला मैदान में संगठित की, इस रैली में देश भर से 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने हिस्सेदारी की। रैली ने एक ज्ञापन पारित किया जिसमें नई पेंशन सिस्टम के सभी नकारात्मक आयामों को लिखा गया और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के सभी पक्ष समर्थनों को लिखा गया ताकि ज्ञापन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा सके। रैली ने निम्नलिखित गतिविधियों के चलाने का निर्णय लिया जिनका समापन अनिश्चितकालीन हड़ताल और भारत बंद में होगा।

1) नई पेंशन सिस्टम को रद्द करने और परिभाषित एवं गारंटीशुदा पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग पर कर्मचारियों को और जन समर्थन की लामबंदी के लिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा और आने वाले दिनों में उद्योग/कार्यालय/इकाई/ स्थानीय स्तर पर तेज किया जाएगा। इस काम के लिए सोशल मीडिया का पूरी तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

शेष पेज 15 पर...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.